● वर्ष-5
● अंक-253
रायपुर, मंगलवार
09 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों...

टीएमसी को बड़ा झटका

20 तृणमूल सांसद एनडीए के साथ

नईदिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लगभग 20 सांसदों ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन देने का इरादा व्यक्त किया है, जो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गठबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, यह जानकारी बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दी है। सोमवार को दस्तीदार ने एएनआई को बताया कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने अपने बयान के साथ एक थम्स अप इमोजी भी लगाया।

सांसद काकोली घोष ने कहा कि हम 20 सांसद हैं जिन्होंने अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था का अनुरोध किया है, और हम पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, और हम पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल राज्य में व्याप्त अराजकता, कुशासन और बेरोजगारी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मैं ममता बनर्जी के साथ 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वह मेरी मार्गदर्शक, मेरी सलाहकार और मेरी नेता रही हैं, और मैं उनके साथ तब भी था जब वह सत्ता में नहीं थीं। मैंने 2009 से पहले पाँच चुनाव लड़े और हार गया। इसलिए यह कहना बेकार है कि पश्चिम बंगाल में उनके सत्ता में न होने से मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ तब भी था जब वह सत्ता में नहीं थीं। लेकिन उस समय एक ऐसी नीति थी जो पश्चिम बंगाल राज्य के गरीब लोगों के लिए जनहितैषी एजेंडा थी... लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में काम संतोषजनक नहीं रहा है। कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं जो आज साबित हो रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकारी अधिकारियों पर कुछ नेतृत्व की मनमानी के अनुसार काम करने का बहुत अधिक दबाव है, जो किसी राज्य के विकास के लिए अनुकूल कार्य वातावरण नहीं है। अब जनता के फैसले ने मेरी बात को साबित कर दिया है। इसलिए हम राज्य के विकास, राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। यही कारण है कि हम अलग-अलग काम करना चाहते हैं काकोली घोष ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और मैं ममता बनर्जी के साथ 40 साल से काम कर रहा हूँ... यह कहना बेकार है कि पश्चिम बंगाल में उनके सत्ता में न होने से मैंने साथ छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है... पिछले 3-4 सालों में सरकारी अधिकारियों पर कुछ खास नेताओं की मनमानी के अनुसार काम करने का बहुत दबाव था... हम राज्य के विकास, राष्ट्रीय हित और देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम अलग होकर काम करना चाहते हैं।

सभी 20 सांसद लोकसभा में काम नहीं कर पा रहे थे। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन बंगाल में इन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। हमें मतदाताओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनता के हक के लिए यह फैसला जरूरी था।

काकोली घोष, लोकसभा सांसद

बैठकों से जुड़े सांसदों की सूची

सूत्रों के मुताबिक, इन घटनाक्रमों में शामिल सांसदों में प्रसून बनर्जी (हावड़ा), शर्मिला सरकार (बर्धमान पुरबा), अरूप चक्रवर्ती (बांकुरा), कालीपद सोरेन (झारग्राम), जगदीश चंद्र बसुनिया (कूच बिहार), काकोली घोष दस्तीदार (बारासात), पार्थ भौमिक (बैरकपुर), बापी हलदर (मथुरापुर), शताब्दी रॉय (बीरभूम), असित कुमार मल (बोलपुर), जून मालिया शामिल हैं। (मेदिनीपुर), अबू ताहेर खान (मुर्शिदाबाद), और खलीलुर रहमान (जंगीपुर)। हालाँकि, टीएमसी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि के सांसदों के लिए किसी भी नए राजनीतिक संगठन में शामिल होना मुश्किल हो सकता है, और सुझाव है कि उनमें से कम से कम कुछ अंततः पार्टी में लौट सकते हैं।

सुखेंदु रॉय के इस्तीफे से हलचल

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उस पर व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं पर घोर अत्याचार और शासन में पूर्ण विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त गंभीर अराजकता का भी जिक्र किया।

12 सालों में आए भारत में बड़े बदलावः मोदी

■ सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर किया साझा

नईदिल्ली। नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे होने पर अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और नीतियों को लेकर एक्स पर पोस्ट की। उन्होंने पोस्ट में कहा कि इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इन सभी के केंद्र में गरीब और वंचित वर्ग का कल्याण रहा है। पीएम मोदी ने लिखा हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं और हमारी कोशिश यही रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो दशकों से पीछे छूट गए थे।

उन्होंने कहा कि जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जलजीवन मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य योजनाओं तक हर पहल का मकसद बस यही रहा है कि लोगों को सम्मान और अवसर मिलें। पीएम ने आगे लिखा कि यह भी खुशी की बात है कि गरीबों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। इससे कार्यक्षमता बढ़ी है और शासन-व्यवस्था में भरोसा मजबूत हुआ है।वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर कहा कि गरीब कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने 12 साल गरीब कल्याण में अन्न योजना, पीएम आवास, जनधन, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधा, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है।

शाह ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर के जरिए देश के गरीबों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़कर 'विकसित भारत' की मजबूत नींव का निर्माण किया जा रहा है।

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के जोरा मॉल में आयोजित 'भारत भाग्य विधाता' फिल्म की प्री-लॉन्च स्क्रीनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय एवं परिजन भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रख्यात अभिनेत्री एवं सांसद सुश्री कंगना रनौत, फिल्म के निर्देशक श्री मनोज तापड़िया सहित फिल्म जगत से जुड़े कलाकार, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। (विस्तृत समाचार पेज 8 पर)

छत्तीसगढ़ के तीन जवान होंगे शौर्य चक्र से सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के लिए आज गर्व का बड़ा दिन है। राज्य के तीन जांबाज जवानों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनमें असम राइफल्स के जवान भोजराम साहू, पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। तीनों को अलग-अलग अभियानों में अदम्य साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है।

असम राइफल्स में पदस्थ जवान भोजराम साहू ने मणिपुर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाई थी। जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2024 को मणिपुर के टेंगनोपाल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब सुबह 9:30 बजे आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान भोजराम साहू को गोली भी लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार जवाबी फायरिंग करते रहे। उनकी बहादुरी के चलते आतंकियों को पीछे हटना पड़ा। इस ऑपरेशन में तीन आतंकियों को मार गिराया गया था।

भोजराम साहू बालोद जिले के आदिवासी विकासखंड डौंडी के ग्राम डोरीटोला के निवासी हैं। उनके शौर्य पर पूरे छत्तीसगढ़ को गर्व है।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख को भी आज शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। दोनों अधिकारी लंबे समय से बस्तर और राजनांदगांव के दुर्गम जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस विभाग में उन्हें नक्सल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। जानकारी के मुताबिक निरीक्षक लक्ष्मण केवट अब तक 97 नक्सलियों के खिलाफ सफल अभियानों का हिस्सा रह चुके हैं, जबकि निरीक्षक रामेश्वर देशमुख 56 नक्सलियों के विरुद्ध हुई कार्रवाइयों में अहम भूमिका निभा चुके हैं।दोनों अधिकारियों की बहादुरी का सबसे बड़ा उदाहरण 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के हापाटोला जंगल में देखने को मिला था। यहां सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सल विरोधी अभियान को अंजाम दिया था। इस मुठभेड़ में 15 महिला नक्सलियों समेत कुल 29 नक्सली मारे गए थे। इसे छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी इतिहास के सबसे सफल अभियानों में से एक माना जाता है। ऑपरेशन के दौरान निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख ने खुद जंगल के भीतर मोर्चा संभालते हुए जवानों का नेतृत्व किया था। उनकी रणनीति और नेतृत्व के चलते सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली।

प्रमुख समाचार

उज्ज्वला योजनाः लाभार्थियों को मिलेगा 300 डीबीटी का लाभ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले चार रिफिल पर प्रति सिलिंडर 300 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, उज्ज्वला योजना वाले एक आम परिवार में औसतन साल भर में लगभग चार रिफिल सिलिंडर की खपत होती थी। पहले पीएमयूवाय लाभार्थियों को साल में 9 रिफिल पर डीबीटी मिलता था। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सालाना मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलिंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव परिवारों द्वारा औसतन इस्तेमाल की जाने वाली गैस की मात्रा को ध्यान में रखकर किया गया है। मई 2016 में शुरू की गई इस प्रमुख योजना के तहत, लाभार्थियों को शुरू में हर साल 14.2 किलोग्राम वाले 12 सब्सिडी वाल एलपीजी सिलिंडर मिलते थे। पिछले साल इस कोटे को घटाकर 9 सिलिंडर कर दिया गया था और अब इसे और कम करके चार कर दिया गया है।

नेपाल बॉर्डर के पास से टीएमसी नेता जहांगीर खान गिरफ्तार

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कई दिनों से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, खान को भारत-नेपाल सीमा (नेपाल बॉर्डर) के पास एक इलाके से सोमवार सुबह तड़के पकड़ा गया। खुफिया जानकारी के आधार पर एसटीएफ काफी समय से उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए थी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक, जहांगीर खान के खिलाफ पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस को काफी समय से उनकी तलाश थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने खान को उनके खिलाफ़ दर्ज कई आपराधिक मामलों में पुलिस की सख्त कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली थी। कोर्ट ने 18 मई को खान को सख्त कार्रवाई से राहत दी थी।

पुणे में 11 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

पुणे। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में 11 जून को पुणे में प्रदर्शन करेगी। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आइए पुणे में मिलें! जय महाराष्ट्र। वहीं, सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया, कॉकरोच महाराष्ट्र की शैक्षिक राजधानी पुणे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। पुणे के कितने कॉकरोच इसमें शामिल होंगे? हाल ही में नेपाल और बांग्लादेश में हुए जेन-जी प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर दीपके ने रविवार को कहा था कि सीजेपी का आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा है और इसकी तुलना पड़ोसी देशों में हुए प्रदर्शनों से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सीजेपी विशेष रूप से जेन जी के लिए है और किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेगी। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने देश में कथित पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए 6 जून को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रदर्शन किया था।

निशांत कुमार ने विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन किया

पटना। बिहार में विधान परिषद चुनाव होने वाला है। इसे लेकर सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन कई उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। एनडीए की बात करें तो, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार विधानसभा संजय झा के साथ पहुंचे। विधानसभा में उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, विधान परिषद सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने आया हूं। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उसके लिए धन्यवाद। पिताजी ने जो विकसित बिहार का सपना देखा है, उसे पूरा करूंगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता और पावर स्टार पवन सिंह ने भी आज नामांकन किया। पवन सिंह अपनी लगभग 2.15 करोड़ रुपये की लग्जरियस लैंड क्रूजर गाड़ी से विधानसभा पहुंचे थे। इस वजह से कई लोगों का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही इस दौरान उनके समर्थकों और अन्य नेताओं की भी भारी भीड़ दिखी। पवन सिंह के साथ उनके बड़े भाई गुड्डू सिंह भी पहुंचे थे।

राम मंदिर ट्रस्ट का अखिलेश यादव को जवाब

लखनऊ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें मंदिर के दान में करोड़ों रुपये गायब होने की बात कही गई थी। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि सभी लेन-देन विधिवत दर्ज किए जाते हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ संसाधित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। सभी लेन-देन का हिसाब-किताब सावधानीपूर्वक रखा जाता है, और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। दिनेंद्र दास महाराज ने कहा कि आपसी सद्भाव और प्रेम है। राम जी सब कुछ देख रहे हैं। लोग चाहे जो कहें, लेकिन राम लल्ला से संबंधित कार्य पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने आगे कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रस्ट कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है और अब तक कोई उल्लेखनीय अनियमितता नहीं पाई गई है। राय ने एक बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समय-समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा कराता है, जो ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की जाती है।

हिंद महासागर में भारत का गेम चेंजर, बढ़ेगी रणनीतिक ताकत

अंकित सिंह

रक्षा सूत्रों ने सोमवार को बताया कि महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना न केवल भारत के रणनीतिक समुद्री और आर्थिक केंद्र बिंदुओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक होगी। सूत्रों के अनुसार, यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों और समुद्री संचार मार्गों (एसएलओसी) से निकटता का लाभ उठाएगी और एक ओर विदेशी माल ढुलाई बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगी, वहीं दूसरी ओर भारत के रक्षा बलों की मजबूत उपस्थिति को सुविधाजनक बनाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने चार परस्पर जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) के समग्र विकास की परिकल्पना की है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी); संयुक्त उपयोगकर्ता ग्रीनफील्ड हवाई क्षेत्र और नौसेना हवाई अड्डा; टाउनशिप और एक विद्युत संयंत्र शामिल हैं। यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिक्स डिग्री चैनल से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अदन की खाड़ी से मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले समुद्री व्यापार मार्ग पर स्थित है।

विश्व के दो-तिहाई तेल और आधे कंटेनर यातायात के इस संवेदनशील क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण, हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय और बाह्य शक्तियों द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद और अवैध अप्रवासन में वृद्धि के मद्देनजर, जीएनआई परियोजना दक्षिण-पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे भारत की प्रतिष्ठा एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) तथा खोज एवं बचाव (एसएआर) जैसी सौम्य भूमिकाओं के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में मजबूत होगी।

रक्षा सूत्रों ने आगे बताया कि इससे अवैध समुद्री गतिविधियों को रोकने में पुलिस बल की भूमिका को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी - यह परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासागर (क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) सिद्धांत में व्यक्त की है। भारत के महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और समुद्री संचार मार्गों (एसएलओसी) पर स्थित महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए निरंतर समुद्री और हवाई निगरानी और सामरिक कार्रवाई की त्वरित शुरुआत आवश्यक है। रक्षा सूत्रों ने रेखांकित किया कि जीएनआई परियोजना भारत को अपने क्षेत्र के निकट अपनी उपस्थिति बनाए रखने, अपनी संपत्तियों को स्थानांतरित करने, अभियानों का समर्थन करने, निगरानी करने और अग्रिम रसद को बनाए रखने की क्षमता प्रदान करती है।

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी), जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री परिवहन मार्गों में से एक, मलक्का जलडमरूमध्य से महज 40 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, भारत की माल परिवहन संबंधी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगा। रणनीतिक और आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने पिछले नवंबर में भारतीय नौसेना के परिचालन नियंत्रण में इस नए हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह हवाई अड्डा भारत की समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए) और परिचालन पहुंच को इस तरह बढ़ाएगा जो किसी मौजूदा रक्षा सुविधा के अकेले विस्तार से पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता।

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए, कैम्पबेल खाड़ी में स्थित इहुड़ बाज़ सहित पांच वैकल्पिक स्थलों का स्थलाकृति, निर्माण में बाधाएं, आदिवासी आबादी पर प्रभाव, वनस्पति और जीव-जंतुओं जैसे मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद अंततः गलाथिया खाड़ी को चुना गया।

पीडिया के जंगलों में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई

बीजापुर के पीडिया में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी ने एक बड़ी सफलता हासिल की.

3 आईईडी व 2 नक्सल डंप बरामद

बीजापुर। बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में नक्सलवाद समाप्त होने के बाद भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। 7 जून को भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे जंगलों में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली।

सूचना के आधार पर कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं द्वितीय कमान अधिकारी कुमार नीरज की देखरेख में एफ/199 कंपनी ने हर्रा/अर्रा (पीडिया) गांव के घने जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। कंपनी कमांडर के बी। पांडा के नेतृत्व में जवानों ने योजनाबद्ध तरीके से इलाके की घेराबंदी कर चरणबद्ध सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया।

अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 3 आईईडी और 2 नक्सल डंप बरामद किए गए।

तलाशी में मिले डंप से आईईडी निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे गन पाउडर, जिलेटिन स्टिक, कमर्शियल डेटोनेटर के साथ 15 मेडिकल आइटम समेत कुल 21 प्रकार की सामग्री जब्त की गई। यह सामग्री नक्सलियों सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई थी।

सुरक्षाबलों ने पूरे अभियान के दौरान अत्यंत सतर्कता बरती, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

बता दें कि कि हर्रा/अर्रा और आसपास का क्षेत्र पूर्व में नक्सली गतिविधियों के लिए संवेदनशील रहा है, लेकिन लगातार चल रहे अभियानों के चलते अब यहां नक्सल प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है।

सीआरपीएफ की 199वीं वाहिनी द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। बल के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की सुरक्षा, शांति और विकास सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है।

भविष्य में भी इस तरह के अभियानों को और ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित कर नक्सल गतिविधियों पर पूर्णत: अंकुश लगाने के प्रयास जारी रहेगा।

पुलिस-युवक विवाद में 3 डीएसपी की जांच समिति गठित

धमतरी। धमतरी में पुलिस और पत्नी और बेटे के साथ बाइक पर जा रहे युवक के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले की जांच के लिए धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने तीन डीएसपी की कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही मामले में शामिल पुलिसकर्मियों और युवक को नोटिस जारी किया गया है। मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन के पास 5 जून की रात करीब एक बजे का बताया जा रहा है।

वायरल वीडियो में अर्जुनी थाना प्रभारी और उनके स्टाफ की एक युवक से तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मामले में सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने वाले युवक ने घटनाक्रम को लेकर अब तक कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन डीएसपी की कमेटी बनाई है। कमेटी का नेतृत्व डीएसपी मोनिका मरावी करेंगी, जिनके साथ डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर और डीएसपी यशकरण ध्रुव पूरे घटना की जांच करेंगे। टीम जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान लेने के साथ तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेगी। फिलहाल, सभी की नजरें तीन डीएसपी की जांच कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि इस पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक का पकड़ाया गांजा

धमतरी। धमतरी पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 480 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जप्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। नशीले पदार्थ को रायपुर और उत्तर प्रदेश में खपाने की प्लानिंग थी। पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस्तर की तरफ से एक कार और पिकअप वाहन में भारी मात्रा में गांजा भरकर रायपुर की ओर ले जाया जा रहा है। जिसके बाद श्याम तराई नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध वाहनों को रोक कर तलाशी ली गई। गाड़ियों की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में सफेद बोरियों में भरकर गांजा मिला। पुलिस जांच के दौरान 480 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 60 हजार रुपए आंकी गई है। गांजा तस्करी मामले में रायपुर के रहने वाले नौशाद खान, करण साहू, मोहम्मद सादिक और हिमांशु साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए हैं।

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने जगदलपुर में सब्जी खाली करने के बाद पिकअप में गांजा लोड किया। इनका प्लान इस गांजे को रायपुर और उत्तर प्रदेश खपाने का था। इस गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश जारी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

मृतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के आरोप से सास बरी, 7 साल की सजा रद्द

बिलासपुर। दहेज प्रताड़ना और मृतिका को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी सास को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि मृतिका को मौत से ठीक पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा वर्ष 2010 में सुनाई गई 7 साल के सश्रम कारावास की सजा के फैसले को रद्द कर दिया है। यह फैसला जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ द्वारा आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया।

दरअसल, दुर्ग निवासी सोनल का विवाह 18 जून 2006 को मनीष के साथ हुआ था। विवाह के 6 महीने बाद 21 दिसंबर 2006 को सोनल की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता, माता और भाई का आरोप था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनल की सास शशिकला बाफना ने दहेज से नाखुशी जताते हुए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। आरोप लगाया गया था कि मृतका के पति को कोलकाता में नौकरी मिलने के बाद भी सास ने सोनल को तब तक कोलकाता भेजने से मना कर दिया, जब तक कि वह मायके से 10 से 15 लाख रुपए नहीं ले आती। अभियोजन के मुताबिक, घटना के दिन 21 दिसंबर 2006 सुबह सास ने सोनल से मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद सोनल अपने मायके पहुंची और शाम को उसने मायके की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले में दुर्ग पुलिस ने आरोपी सास के खिलाफ धारा 304-बी, दहेज मृत्यु के तहत मामला दर्ज किया था। मार्च 2010 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने आरोपी सास शशिकला बाफना को दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपीलकर्ता सास के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि, घटना के 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। मेडिकल साक्ष्यों के अनुसार, शुरुआत में परिजनों ने ही डॉक्टर को बताया था कि सोनल बाथरूम में गिरने के कारण घायल हुई है।

एमसीबी में अवैध महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार

एमसीबी। अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिरमिरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध महुआ शराब के कारोबार में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 49 लीटर महुआ शराब बरामद किया है। चिरमिरी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिलेभर में अवैध शराब, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान थाना चिरमिरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आमानाला गोदरीपारा निवासी अंकित कुमार उर्फ शन्नी अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब संग्रहित कर उसकी बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और तत्काल आरोपी के घर पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर आंगन में रखी दो बोरियों से कुल 49 पाउच महुआ शराब बरामद की गई। हर पाउच में लगभग एक लीटर शराब भरी हुई थीय इस प्रकार कुल 49 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके पर ही शराब को जब्त कर लिया तथा आरोपी अंकित कुमार उर्फ शन्नी (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

हाथी ने सड़क निर्माण में लगे दो मजदूरों को कुचला, टाइगर रिजर्व में लोनर हाथी ने फैलाई दहशत

कोरिया/एमसीबी। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सोनहत वन परिक्षेत्र अंतर्गत देवसील गांव की आगे बस्ती में सड़क निर्माण कार्य में लगे दो मजदूरों की एक हाथी के हमले में मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं वन विभाग ने जनकपुर रेंज क्षेत्र में एक लोनर (अकेला) हाथी के मूवमेंट की संभावना को देखते हुए ग्रामीणों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है।रविवार रात लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूर दिनभर की मेहनत के बाद खाना खाकर सो रहे थे। मजदूरों ने जंगली जानवरों से बचाव के लिए आग जला रखी थी। इसी दौरान अचानक एक हाथी वहां पहुंच गया और सो रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में 22 वर्षीय गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय अमर सिंह को इलाज के लिए सोनहत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से लगभग चार किलोमीटर पहले ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। मजदूरों और ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी तत्काल मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पंचनामा और अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से निर्धारित सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इधर पार्क परिक्षेत्र जनकपुर के रेंजर राजाराम ने जानकारी दी कि आज हाथी जनकपुर रेंज में विचरण कर सकता है। इसे देखते हुए क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जंगल क्षेत्र में पैदल या मोटरसाइकिल से आवागमन न करें।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा में बदमाशों का कहर एएसआई के बेटे पर चढ़ाई गाड़ी

कोरबा। ऊर्जाधानी में रविवार रात को एक छोटी सी बात पर दो युवकों की जान पर बन आई। कोरबा शहर से लेकर बलगी मोड तक युवकों ने छोटी सी बात पर एक को बोलेरो से कुचलने का प्रयास किया। वहीं जब दूसरे युवक ने इसका विरोध किया तो बोलेरो सवार ने युवक के कनपटी पर पिस्तौल रखी और उसे अधमरा होने तक मारा। पीड़ितों में से एक एएसआई का बेटा है,जिसकी हालत गंभीर है।वहीं दूसरा युवक भी गंभीर रुप से घायल है। इस वारदात में पिस्टलनुमा हथियार का भी इस्तेमाल किया गया है। हवाई फायरिंग का भी आरोप घायल ने लगाया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रयास और लूट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की धर पकड़ करने का प्रयास जारी है। इस वारदात को अंजाम देने में कुछ आदतन बदमाशों का नाम भी सामने आ रहा है। ये घटना रविवार दरमयानी रात एक से तीन बजे के बीच की है। मानिकपुर पुलिस सहायता केंद्र अंतर्गत बुधवारी बायपास मार्ग पर रात करीब 1 बजे कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ काले रंग की कार में मौजूद थे।

जंगली सुअर के शिकार पर वन विभाग का छापा

कोरबा। कटघोरा वनमंडल के पसान वन परिक्षेत्र में जंगली सुअर का शिकार कर पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे लोगों पर वन विभाग ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों पर केस दर्ज किया गया, जबकि कुछ को बचाने के नाम पर रुपये वसूली के आरोप लगे हैं। मामले से जुड़ा डिप्टी रेंजर का वीडियो वायरल होने के बाद डीएफओ कुमार निशांत ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार मामला लैंगा बीट के करी गांव का है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने जंगली सुअर का शिकार किया था। इसके बाद गांव में पार्टी की तैयारी चल रही थी। इसकी सूचना फॉरेस्ट गार्ड राम कुमार कोराम को मिली। सूचना मिलते ही वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। विभाग ने शिकार में शामिल कुछ लोगों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। साथ ही शिकार में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त की गई। इसी बीच मामले से जुड़ा एक कथित स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में डिप्टी रेंजर लैंगा उषा सोनवानी और कुछ ग्रामीण बैठे दिखाई दे रहे।

जमीन बिक्री में फर्जीवाड़ा आर्मी जवान के नाम पर दूसरे को किया पेश

दुर्ग। दुर्ग के पाटन क्षेत्र में संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि की बिक्री से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आर्मी में तैनात अपने सगे भाई की जगह दूसरे व्यक्ति को पेश कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। दुर्ग के पाटन थाना क्षेत्र में संयुक्त स्वामित्व वाली कृषि भूमि की बिक्री में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार को इस मामले के आरोपी ईश्वर दास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी तीन साल से फरार चल रहा था। यह धोखाधड़ी आर्मी में तैनात एक जवान के बड़े भाई ने की थी। उसने अपने भाई की जगह किसी अन्य व्यक्ति को पेश कर जमीन की रजिस्ट्री कराई। पीड़ित जवान ने साल 2023 में पाटन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बड़े भाई पर संयुक्त नाम से दर्ज भूमि बेचने का आरोप था। पुलिस ने जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल की। जांच में पहचान संबंधी दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जी दस्तावेज बनाने का खुलासा हुआ। आरोपी ने इस तरीके से आर्थिक लाभ लेने का प्रयास किया था।

रावत जाति को तुरंत केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग

कोरबा। झेरिया यादव समाज ने रावत जाति को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में तत्काल शामिल करने की मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष जगनीक यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष निरंजन ज्योति से भेंट की। रायपुर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना में ज्ञापन सौंपकर शीघ्र निर्णय की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज के अनेक परिवार रावत उपनाम का उपयोग करते हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची में नाम न होने से युवाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे समाज के हजारों प्रतिभाशाली युवक-युवतियां अवसरों से वंचित हो रहे हैं। जगनीक यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने रावत जाति को केंद्रीय सूची में शामिल करने की अनुशंसा पहले ही भेजी है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है, जिससे समाज में निराशा है। उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अवसर के लिए रावत जाति को तत्काल सूची में शामिल करने की मांग की। यह केवल आरक्षण नहीं।

मनेंद्रगढ़ नपा में विकास कार्यों को लेकर भेदभाव का आरोप

एमसीबी। जिले के नपा में कांग्रेस ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्षदों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नपा कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नपा प्रशासन पर भाजपा समर्थित पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता देने और कांग्रेस पार्षदों के वार्डों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया। धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नपा में विकास कार्य राजनीतिक आधार पर कराए जा रहे हैं, जिससे कई वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि नपा प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला और सभी वार्डों के साथ समान व्यवहार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। कांग्रेस पार्षद, सांसद प्रतिनिधि और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि नपा प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में विकास कार्यों को जानबूझकर प्रभावित कर रहे हैं।

पीडीएस चावल अगर खाने लायक नहीं तो एक्शन ले सरकार

बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा का आरोप है कि सोसायटियों से जो चावल मिल रहा है, उसकी क्वालिटी निम्न स्तर

जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं- संगीता सिन्हा

बालोद। कांग्रेस की तेज तर्रार महिला विधायक संगीता सिन्हा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बालोद विधायक का कहना है कि पीडीएस के तहत इन दिनों जो चावल बांटा जा रहा है उसकी गुणवत्ता काफी खराब है। बघमरा में आयोजित सुशासन चौपाल में मंच से बोलते हुए संगीता सिन्हा ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। विधायक ने कहा कि जब चावल खाने योग्य नहीं है तो ऐसे में गरीबों के बीच ये चावल क्यों बांटा जा रहा है। विधायक संगीता सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकारी राशन दुकानों (सोसायटियों) में मिल रहा चावल इंसानों के खाने योग्य नहीं है। इसके बावजूद लोगों को वितरित किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि जो चावल दिया जा रहा है, वो घटिया किस्म का है और उससे बदबू भी आ रही है। विधायक ने कहा कि ग्रामीण इस बात को लेकर लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि अगर लोग ये घटिया चावल खाएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की व्यवस्था प्रणाली को देश में मॉडल माना जाता है, लेकिन बालोद जिले में गरीबों को जो चावल बांटा जा रहा है, वह पूरी तरह अखाद्य है। जनता की सेहत के साथ यह खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- संगीता सिन्हा, विधायक, बालोद विधायक का कहना है कि जब घटिया चावल को लेकर उन्होने अधिकारियों से शिकायत की तो उनका कहना था कि राइस मिलों से ही इस तरह का चावल उनके पास पहुंच रहा है। विधायक के आरोपों पर अधिकारियों का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राइस मिल वालों की ओर से भी इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

इंजन की गड़गड़ाहट के साथ निकला बदलाव का कारवां

बारनवापारा पहुंचीं 18 महिला बाइकर्स

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का एक संगठित बाइकर्स ग्रुप मोटो क्वींस एडवेंचर रविवार को रायपुर से बारनवापारा अभ्यारण्य पहुंचा।इस विशेष अभियान में 18 महिला बाइकर्स शामिल हुईं, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर यह साबित कर दिया कि महिलाएं अब सिर्फ घर और दफ्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एडवेंचर, पर्यटन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। इस पूरे अभियान की शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है। मोटो क्वींस एडवेंचर की संस्थापक और कांकेर निवासी वनिका (वानी) पिल्लई ने बताया कि नवंबर-दिसंबर 2025 में उन्होंने अकेले बाइक पर कांकेर से नेपाल तक की लंबी यात्रा की थी। यह यात्रा सिर्फ एक एडवेंचर नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और साहस की परीक्षा भी थी। नेपाल यात्रा के दौरान उन्होंने अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। उनकी पोस्ट और वीडियो देखकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने उनसे संपर्क किया। कई महिलाओं ने कहा कि वे भी ऐसी यात्राएं करना चाहती हैं लेकिन उन्हें सही मंच और सहयोग नहीं मिल पाता। यहीं से एक नए विचार ने जन्म लिया और मोटो क्वींस एडवेंचर की नींव रखी गई। आज यह समूह तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसमें 18 सक्रिय महिला सदस्य जुड़ चुकी हैं। इनमें छात्राएं, प्रोफेशनल महिलाएं, गृहिणियां और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं।इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसमें शामिल अधिकांश महिलाएं अपने घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाने के बाद इस अभियान का हिस्सा बनीं। कई महिला बाइकर्स ने बताया कि शुरुआत में परिवार के लोग चिंतित थे, लेकिन अब वे गर्व महसूस करते हैं कि उनकी बेटियां, बहनें और पत्नियां समाज के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का कहना है कि यह यात्रा सिर्फ बाइक चलाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक बदलाव का अभियान है।

संक्षिप्त समाचार

साय कैबिनेट की बैठक में आज हो सकते हैं महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंगलवार 9 जून को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें स्वास्थ्य,तबादला सहित अनेक अहम विषयों पर चर्चा के बाद इस पर मुहर लगाई जा सकती है। कैबिनेट की बैठक 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े प्रस्तावों पर भी सरकार फैसला ले सकती है। लंबे समय से लंबित प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा योजना को हरी झंडी दे सकती है। इस योजना के लागू होने पर राज्य के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को इलाज के दौरान पहले भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी और सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसी के साथ कैबिनेट में तबादला नीति पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है,जिस पर मुहर लग सकती है।

राज्यपाल से अखिल भारतीय गोंड़वाना गोंड़ महासभा के पदाधिकारियों ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार को यहां लोकभवन में अखिल भारतीय गोंड़वाना गोंड़ महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री आर.एन. ध्रुव के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने ग्राम गोड़ खपरी जिला धमतरी में ग्रामीणों के श्रम दान से निर्मित सिंचाई परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आमंत्रित किया। इस अवसर पर श्री एस. पी ध्रुव ,श्री नारायण ध्रुव और श्री रामनरेश भी उपस्थित थे।

डेका से छत्तीसगढ़ कायाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से सोमवार को यहां लोकभवन में छत्तीसगढ़ कायाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भेंट कर सेंध लेक नवा रायपुर में 9 एवं 10 जून 2026 को आयोजित होने वाले अस्मिता जोनल लीग प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आमंत्रित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कायाकिंग-कैनोइंग एसोसिएशन के सहसचिव श्री प्रशांत सिंह रधुवंशी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में 165 अफसर-कर्मचारियों का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के उद्देश्य से 165 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है। तबादला सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार 46 परिवहन निरीक्षकों, 50 परिवहन उपनिरीक्षकों, 16 सहायक उपनिरीक्षकों, 35 प्रधान आरक्षकों और 18 आरक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। विभाग ने इस व्यापक फेरबदल को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। अधिकारियों के अनुसार इस बदलाव से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और कार्यकुशलता में सुधार आएगा। तबादला सूची में कई महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं भी की गई हैं। कोरबा उडऩदस्ता में पदस्थ परिवहन निरीक्षक अनुपम पटेल को नारायणपुर का प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दुर्ग में पदस्थ सनत कुमार जागड़े को बीजापुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक दृष्टि से इन दोनों जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कृष्ण कुमार चौबे को अंबिकापुर से चिल्फी चेकपोस्ट, वैभव शुक्ला को रायपुर से रामानुजगंज और मोहम्मद आबिद खान को कोटा से धनपुंजी चेकपोस्ट स्थानांतरित किया गया है। वहीं संतोष कुमार राठौर, चंद्र कुमार साहू और अरुणा साहू को रायपुर उडऩदस्ता में नई पदस्थापना दी गई है। महेंद्र कुमार कुलदीप को परिवहन कार्यालय बिलासपुर, राजेंद्र कुमार बर्मन को पाटेकोहरा चेकपोस्ट से रायगढ़ उडऩदस्ता, केशव प्रसाद राजवाड़े को दुर्ग उडऩदस्ता और जितेंद्र भूषण को पाटेकोहरा चेकपोस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परिवहन विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

भांठागांव फ्लाईओवर पर ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, कोई हताहत नहीं

रायपुर। रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के दौरान राजधानी रायपुर के रिंग रोड नंबर-1 स्थित भांठागांव फ्लाईओवर पर ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भांठागांव फ्लाईओवर पर एक कार चालक रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही डीडी पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करने के साथ मामले की जांच में जुट गई।

ईमानदारी और मेहनत साहू समाज की पहचान, इसे बनाकर रखें : अरुण साव

■ **उप मुख्यमंत्री कर्मा महोत्सव में हुए शामिल, तैलीय सदन का किया लोकार्पण**

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव किरंदुल में तहसील साहू संघ द्वारा आयोजित कर्मा महोत्सव, नवीन सामाजिक भवन नामकरण एवं लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सामाजिक पदाधिकारियों के साथ एक करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भव्य तैलीय सदन का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, दंतेवाड़ा के विधायक श्री चौतराम अटामी और किरंदुल नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रुबी शैलेन्द्र सिंह भी महोत्सव में शामिल हुईं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कर्मा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि किरंदुल में छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य साहू समाज का भवन बना है। इस भवन का रोज उपयोग हो, ऐसी व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और मेहनत साहू समाज की ताकत और विशेषता है। हमारी इस पहचान को बनाकर रखना है।

श्री साव ने कहा कि सभी समाजों के साथ साहू समाज का आत्मीय संबंध है। यह सभी के साथ मिलकर चलने वाला समाज है। साहू समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश-विदेश में समाज के युवा अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भक्त माता कर्मा के बताए मार्ग पर चलकर हमें समाज को ऊंचाईयों पर पहुंचाना है।

छत्तीसगढ़ तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू ने अपने संबोधन में कहा कि साहू समाज का तेल निकालने का पुश्तैनी काम रहा है। हमारे इस पुश्तैनी व्यवसाय को पुनर्स्थापित करना चाहिए। उन्होंने समाज के लोगों को तेल निकालने की मशीन लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि तेल निकालने की मशीनों पर सरकार द्वारा 35 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। समाज के लोग इसका लाभ लेकर तेल निकालने का उद्यम कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

विधायक श्री चौतराम अटामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज के लोग किरंदुल में सक्रियता से काम कर रहे हैं। समाज के 300 परिवार यहां रहते हैं। उन्होंने समाज की मांग पर शैक्षणिक कार्य के लिए कमरा बनाने की घोषणा की। किरंदुल नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती रुबी शैलेन्द्र सिंह, किरंदुल तहसील साहू समाज के अध्यक्ष श्री टीकमचंद साहू और छत्तीसगढ़ साहू समाज के संगठन सचिव श्री ओमप्रकाश साहू ने भी कर्मा महोत्सव को संबोधित किया।

कार्यक्रम में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए श्री लालाराम साहू को समाजरत्न सम्मान दिया गया। माता कर्मा प्रांगण में दीवारों कर कलाकृति बनाने वाले कलाकार श्री कामता राम कोर्राम को भी सम्मानित किया गया। भगवताचार्य श्रीमती यामिनी देवी साहू, लोक गायिका सुश्री आरू साहू, पार्षद श्री विनोद साहू और तहसील साहू समाज के संरक्षक श्री ओम साहू सहित साहू समाज के प्रदेशभर के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है।

बैठक में ई-ऑफिस, ई अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत, सेवा सेतु, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने एवं कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से ली।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव श्री पी.दयानंद, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव सुश्री आर. शंगीता, गृह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव सुश्री ईफ्फत आरा सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

मर्दापाल अंचल को विकास कार्यों की सौगात

■ **वनमंत्री केदार कश्यप ने किया भूमिपूजन और लोकार्पण**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए मर्दापाल अंचल की 23 ग्राम पंचायतों में 4 करोड़ 6 लाख 67 हजार रूपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर इन बुनियादी विकास कार्यों का विधि-विधान से भूमिपूजन किया।

इन स्वीकृत विकास कार्यों में मुख्य रूप से सड़क, पुलिया, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, रंगमंच और अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को एक नई गति प्राप्त होगी।

ग्राम चांगे लगभग 77.96 लाख रूपए की लागत से पुलिया, नवीन प्राथमिक शाला भवन, सीसी सड़क, रंगमंच और सामुदायिक भवन निर्माण। ग्राम मूलनार में लगभग 90.79 लाख रूपए की लागत से पुलिया, बाउंड्रीवाल, सीसी सड़क तथा अन्य बुनियादी ढांचागत विकास, ग्राम बड़ेकुरुषनार लगभग 88.14 लाख रूपए की लागत से पुलिया, रंगमंच, आहाता, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र, नवीन प्राथमिक शाला भवन, सांस्कृतिक भवन और पंचायत भवन का निर्माण, ग्राम बेचा लगभग 21.79 लाख की लागत से रंगमंच एवं माध्यमिक शाला भवन का भूमिपूजन और लोकार्पण, अन्य ग्राम पंचायतें रानापाल, कोंगेरा, मुंगवाल और चेरंग में 28 लाख रूपए तथा हथकली, मटवाल, पेरमापाल, नरिहा और आदनार में लगभग 1 करोड़ रूपए की लागत से सामुदायिक भवन, सीसी सड़क, शाला भवन और पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया, शामिल है।

इस अवसर पर वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सुदूर गांवों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, शिक्षा, सामुदायिक अधोसंरचना और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। श्अटल डिजिटल सुविधा केंद्रोंश् के माध्यम से अब ग्रामीणों को सभी जरूरी शासकीय सेवाओं का लाभ उनके अपने गांव में ही मिल सकेगा।

अमित जोगी द्वारा धार्मिक भावनाएं आहत करने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में शिकायत दर्ज

रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी के खिलाफ धार्मिक भावनाएँ भड़काने, साक्ष्य मिटाने और लोक सेवक को झूठी जानकारी देकर भ्रमित करने के संबंध में एक लिखित शिकायत सौंपी गई है। यह शिकायत रविवार को भाजपा आईटी सेल के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शैलेश दीक्षित द्वारा औपचारिक रूप से दर्ज कराई गई है।

श्री दीक्षित द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार, यह पूरा विवाद बीते 27 मई 2026 को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के अवसर पर शुरू हुआ। आरोप है कि अमित जोगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बकरीद की शुभकामनाएँ देते हुए एक पोस्टर प्रसारित किया था। इस पोस्टर में एक बकरी के साथ

गाय का भी चित्र शामिल था। इस आपत्तिजनक चित्र को लेकर सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भारी विरोध शुरू हो गया, क्योंकि इससे बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्था को गहरी ठेस पहुँची थी। जनता के व्यापक विरोध और आक्रोश को देखते हुए अमित जोगी ने करीब दो घंटे बाद उस मूल फोटो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया। इसके बाद, उन्होंने बिना गाय वाली नई फोटो पोस्ट कर दी। अपनी इस चूक और जन-आक्रोश से खुद को निर्दोष साबित करने के उद्देश्य से उन्होंने उसी दिन गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही क्षेत्र के एक थाने में एक कथित तौर पर झूठी और मनगढ़ंत प्राथमिकी भी दर्ज करा दी। श्री दीक्षित ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सोशल मीडिया और फेसबुक/मेटा के सर्वर से इस एडिट हिस्ट्री की तकनीकी जाँच कराई जाए, जिससे सच सामने आ सके। उन्होंने इस मामले में अमित जोगी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम, धार्मिक भावनाएं भड़काने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा लोक सेवक को झूठी सूचना देने की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का प्रभारी सचिव ने किया निरीक्षण

रायपुर। निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का निरीक्षण जशपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने आज जशपुर में निर्माणाधीन जगदेव राम उरांव कल्याण आश्रम चिकित्सालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं तेज गति से संचालित किए जाने पर संबंधित एजेंसी और अधिकारियों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि अस्पताल के पूर्ण होने के बाद यह क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगा तथा स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, एसडीएम जशपुर श्री विश्वास राव मस्के, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालन अभियंता श्री प्रफुल्ल चौरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि इस अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण एनटीपीसी लारा के सीएसआर मद से लगभग 35 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। अस्पताल का भूमिपूजन 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया था। वर्तमान में छह मंजिला भवन के ग्राउंड फ्लोर सहित चार मंजिलों की ढलाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।

सुशासन तिहार से मजबूत हो रहा जनविश्वास : डॉ. किरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं दिखाई दे रही, बल्कि गाँव की चौपालों, गलियों और दूरस्थ वनांचलों तक पहुँचती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहा सुशासन तिहार अब महज सरकारी अभियान नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच भरोसे को मजबूत करने वाला जन-आंदोलन बनता जा रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ.(श्रीमती) बघेल ने सोमवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इसे केवल शिकायत निवारण कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे शासन की जवाबदेही और संवेदनशीलता से जोड़ा है। यही वजह है कि प्रदेश के सुदूर आदिवासी इलाकों से लेकर शहरों के वार्डों तक यह संदेश तेजी से गया है कि अब सरकार स्वयं लोगों के द्वार तक पहुँच रही है। इस अभियान का मूल उद्देश्य भी स्पष्ट है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव और देरी के पहुंचाना। डॉ. बघेल ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड सुधार, सीमांकन,

राशन कार्ड, पेंशन, पेयजल, बिजली या प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। सुशासन तिहार में प्रशासन गाँवों और मोहल्लों तक पहुँच रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के क्लस्टर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर बनाकर विशेष शिविर आयोजित किए है।

डॉ. बघेल ने कहा कि सुशासन तिहार में इस वर्ष विशेष रूप से उन मुद्दों पर फोकस किया गया है, जो सीधे आम लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े हैं। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं तथा लोगों को तत्काल राहत मिल रही है। सुशासन तिहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार गाँवों का दौरा कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं और सीधे ग्रामीणों के बीच पहुँच रहे हैं। कई स्थानों पर वे बिना किसी औपचारिक मंच के पेड़ों की छाँव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान जिला मुख्यालयों में लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। शिविरों में प्राप्त आवेदनों की निगरानी की जा रही है और उनके निराकरण की समय-सीमा तय की गई है। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अधिकारी अब केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गांवों में जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार 2026 केवल शिकायत निवारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनविश्वास निर्माण का व्यापक अभियान बन चुका है। गाँवों में लग रही चौपालें अब संवाद और सहभागिता का मजबूत माध्यम बन रही हैं। लोगों को यह महसूस हो रहा है कि शासन उनकी बात सुन रहा है और समस्याओं के समाधान के लिए गम्भीर भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार का केंद्र सत्ता नहीं, बल्कि जनता है। यही भावना इस अभियान को विशेष बनाती है और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता भी मानी जा रही है।

कांग्रेस की परंपरा और संस्कार में ही गुटबाजी : जायसवाल

नेता प्रतिपक्ष महंत का पलटवार- सामूहिक नेतृत्व में हम करते हैं विश्वास

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कवायद शुरू हो गई है। पद के लिए कई दावेदार हैं, कुछ मुखर हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे गुप-चुप तरीके से अपने काम में जुटे हैं। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल के इस अहम पद को लेकर जहां भाजपा नेता और मंत्री तंज कस रहे हैं, तो कांग्रेस नेता भी उसी तंज भरे लहजे में जवाब दे रहे हैं।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में कई और नेता शामिल होने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले 3 सालों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मुद्दा प्रदेश में घूम रहा है। अब यह बोरिंग चेप्टर हो चुका है। कांग्रेस को पूरे प्रदेश ने ही भुला दिया है। कांग्रेस की गतिविधियों को याद रखना, बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। जब से मैंने होश संभाला है, देख रहा कि इनमे आपसी मतभेद ही रहता है। कांग्रेस की परम्परा और संस्कार में ही गुटबाजी है। यहीं समय- समय पर उभरकर आता है।

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि हमारे में तो ऐसा नहीं है। वो अभी ङ्क अभी आए हैं, इनको कहाँ से पता लग गया। कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम जो चार-पांच लोग अगुवाई कर रहे हैं, उनमें सब ठीक है। सामूहिक नेतृत्व में हम विश्वास करते हैं। चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में होगा। कांग्रेस में कुछ भी निर्णय होता है, तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर होता है। डॉ. महंत ने कहा कि आने वाले समय में जिन ङ्क जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें प्रदेश अध्यक्ष बदलने की पूरी संभावना है। छत्तीसगढ़ के बारे में भी चर्चा है। लेकिन जब तक राहुल गांधी का यहां दौरा और जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण नहीं हो जाता, तब तक इसकी कोई जरूरत नहीं है।

चरण दास महंत ने इसके साथ खाद-बीज को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि सरकार का सब ठीक है, कहना उचित नहीं है। निचले स्तर पर समस्या अभी भी है, गांव में तकलीफ है। गांव में काम नहीं हो रहा है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है। इसकी चिंता सबको है, लेकिन मंत्रीगणों को नहीं दिख रहा है। इसमें गंभीरतापूर्वक मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए जो आज की जरूरत है। इंडियन एलायंस की बैठक पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि आज दिल्ली में इंडिया एलायंस की बैठक है। देश में महंगाई, डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस और खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों पर चर्चा होगी। देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका और आगे की रणनीति पर मंथन होगा।

राजधानी में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये बढ़ाई गई उपकेंद्र की क्षमता

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) ने राजधानी सहित दुर्ग की विद्युत पारेषण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 220/132 केवी उपकेंद्र, भिलाई में 160 एमवीए क्षमता के पावर ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की गई।

इसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने बटन दबाकर ऊर्जीकृत कर दिया। प्रबंध निदेशक श्री शुक्ला ने परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, अभियंताओं एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सीएसपीटीसीएल राज्य की विद्युत पारेषण प्रणाली को आधुनिक, सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर मुख्य अभियंता (सब-स्टेशन) श्री अब्राहम वर्गीज, मुख्य अभियंता (सिविल) श्री संजय तिवारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री आर. के. तिवारी सहित सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीडीसीएल के अनेक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि योजना के अंतर्गत पूर्व स्थापित 125 एमवीए पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को बढ़ाकर 160 एमवीए किया गया है।

कांग्रेस पार्टी में कुर्सी की जिद, बगावती बुढ़ापा और

दिलीप कुमार पाठक

भारतीय राजनीति का एक सीधा सा नियम है। एक समझदार नेता वह नहीं है जिसे सिर्फ आगे बढ़ना आता हो, बल्कि वह है जिसे यह पता हो कि कब और कितनी इज्जत के साथ दो कदम पीछे हट जाना है। आज की आपाधापी और कुर्सी से चिपके रहने की राजनीति के बीच, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जो समझदारी दिखाई है, वह काबिले तारीफ है। उन्होंने देश के बाकी बुजुर्ग नेताओं को एक ऐसा सधा हुआ संदेश दिया है, जो न सिर्फ उनकी इज्जत को बढ़ाता है बल्कि दूसरों के लिए एक सबक भी है।राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि पार्टी अब शायद दिग्विजय सिंह को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी। अमूमन ऐसे मोड़ पर बड़े-बड़े नेता या तो बगावत पर उतर आते हैं या फिर कोने में बैठकर नाराजगी जताने लगते हैं। लेकिन दिग्गी राजा ने जिस अक्लमंदी से अपनी साख और सम्मान को बनाए रखा है, वह उनकी राजनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। लोकतंत्र में कोई उनकी विचारधारा से अलग सोच रख सकता है, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ और सही टाइमिंग के मामले में वे आज भी बेजोड़ हैं। वे जानते हैं कि जब हवा का रुख बदल रहा हो, तो खुद को कैसे संभाला जाता है। पद पर न रहकर भी संगठन में अपनी साख को कैसे बरकरार रखा जाता है, यह कला दिग्विजय सिंह ने बखूबी दिखाई है। इसके ठीक उलट, जब हम मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके ही समकालीन नेता कमलनाथ को देखते हैं, तो स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ पर भरोसा जताकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी थी। लेकिन अपनी जिद और कुंठा के कारण कमलनाथ ने न सिर्फ सरकार गंवाई, बल्कि धीरे-धीरे प्रदेश में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाल ही में एक राज्यसभा सीट के लिए दिल्ली से भोपाल तक की गई उनकी भागमभाग को सबने देखा। इतनी दौड़-धूप करने के बाद भी अंत में उन्हें खाली हाथ रहना पड़ा और सीट नहीं मिली, जिससे राजनीतिक गलियारों में उनकी जो किरकिरी हुई वह अलग। खुद को समय के अनुसार न ढालने की यह कुंठा किसी भी कद्दावर नेता के बने-बनाए इतिहास को धूमिल कर देती है।यही हाल राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का भी है। जब कोई नेता यह मान बैठता है कि पूरा प्रदेश उसकी मुट्ठी में है, तो वहीं से उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल शुरू होती है। जीवनभर सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद भी जब एक बड़ा नेता युवाओं का रास्ता रोकने लगता है, तो वह खुद अपनी इज्जत कम कर लेता है। राजस्थान में सचिन पायलट के प्रति उनकी नफरत और पदों के लिए कभी न खत्म होने वाली भूख ने उनके कद को बहुत छोटा कर दिया है। सवाल यह है कि जब आप खुद पूरी जिंदगी मलाईदार पदों पर रहे, तो आज युवाओं की महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं ? गहलोत के बदले हुए सुर और उनकी भाषा साफ इशारा कर रही है कि वे अब पार्टी से अलग रास्ता तलाश रहे हैं। अपनी राजनीति बचाने की ज़िद में वे अपनी ही इज्ज़त दांव पर लगा चुके हैं। अब होगा यह कि या तो वे खुद ही बाहर निकल जाएंगे, या फिर पार्टी उन्हें खुद किनारे लगा देगी।अशोक गहलोत और कमलनाथ का यह रुख कोई पहला उदाहरण नहीं है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जो नेता समय रहते मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं आए, उन्होंने अपनी ही जिद से अपना राजनीतिक बुढ़ापा खराब कर लिया। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और जम्मू-कश्मीर के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।

पाक के बाद अब बांग्लादेश से रक्षा संबंध बना रहा तुर्किये

नीरज कुमार दुबे

दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक बिसात पर अब एक नया और बेहद खतरनाक समीकरण तेजी से उभर रहा है। भारत विरोधी रवैये के लिए लंबे समय से चर्चित तुर्किये अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बांग्लादेश के साथ भी अपने रक्षा और सामरिक रिश्तों को तेजी से विस्तार देना शुरू कर दिया है। ढाका पहुंचे तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने जिस तरह बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, उसने नई दिल्ली की चिंता और गहरा दी है। इस बयान को भारत के चारों ओर रणनीतिक दबाव बनाने की सुनियोजित चाल के रूप में देखा जा रहा है।

तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है। बांग्लादेश ने तुर्किये को रक्षा सामग्री निर्माण में निवेश का खुला न्योता दिया है। दोनों देशों ने पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह वही तुर्किये है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्षों तक भारत विरोधी मोर्चेबंदी की, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया और इस्लामी सहयोग संगठन के मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया।

उधर, दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुर्किये अब भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के साथ समानांतर सामरिक रिश्ते बना रहा है। यह दो तरफा दबाव की रणनीति जैसी दिखाई देती है। पाकिस्तान पहले से ही तुर्किये के रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का लाभ उठा रहा है। अब यदि वही ढांचा बांग्लादेश तक पहुंचता है, तो भारत के लिए सुरक्षा समीकरण और जटिल हो जाएंगे। खास तौर पर तब, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार अपनी विदेश नीति को नए ढंग से गढ़ने की कोशिश कर रही है।

इसके अलावा, तुर्किये और बांग्लादेश के बीच केवल रक्षा सहयोग ही नहीं, बल्कि आर्थिक और संस्थागत साझेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। दोनों देश व्यापार को तेरह अरब डॉलर से बढ़ाकर बीस अरब डॉलर तक ले जाने की तैयारी में हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तुर्किये को निवेश का निमंत्रण दिया गया है। वस्त्र, दवा निर्माण, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। ढाका में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अस्पताल और नर्सिंग संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि तुर्किये केवल सैन्य साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करने की नीति पर काम कर रहा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्किये दक्षिण एशिया में खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली संरक्षक के रूप में स्थापित करना चाहता है। रोहिंग्या मुद्दे पर उसकी सक्रियता, गाजा पर आक्रामक बयानबाजी और बांग्लादेश के साथ मानवीय सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार और भारत की सामरिक चुनौती को बढ़ाना है।

वैसे तो तुर्किये लगातार यह कह रहा है कि भारत को उसके पाकिस्तान से रिश्तों की वजह से उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन असली सवाल भरोसे का है। राष्ट्रपति एर्दोआन कई बार खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तुर्किये ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा रिश्ते भी काफी मजबूत कर लिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरण और ड्रोन तक मुहैया कराए थे। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आए जिन कई ड्रोनों को मार गिराया था, उनमें तुर्किये में बने ड्रोन भी शामिल थे। ऐसे में तुर्किये का भारत से दोस्ती और संतुलन की बात करना नई दिल्ली को एक सोची समझी रणनीतिक चाल जैसा लगता है। यही वजह है कि भारत भी अब तुर्किये को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है।

दरअसल, भारत ने हाल के वर्षों में साइप्रस और ऑर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत किया है। ऑर्मेनिया अब भारतीय हथियारों का बड़ा खरीदार बन चुका है। साइप्रस के साथ भी भारत रणनीतिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। यह सीधे-सीधे तुर्किये को संदेश है कि यदि अंकारा भारत के पड़ोस में दखल बढ़ाएगा, तो नई दिल्ली भी तुर्किये के सामरिक क्षेत्र में जवाबी दबाव बनाएगी। जिस तरह तुर्किये पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह भारत भी तुर्किये के विरोधी या प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। यह नई शीत प्रतिद्वंद्विता का संकेत है।

उधर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति भी इस समय भारत के लिए गहरी चिंता का विषय बनती जा रही है। भारत की ओर से सबसे पहले आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण मिलने के बावजूद रहमान ने पहले मलेशिया और फिर चीन जाने का फैसला किया। ढाका ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अब केवल भारत पर निर्भर रहने वाली नीति से आगे बढ़ना चाहता है। खास बात यह है कि चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना समेत कई बड़े रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। साथ ही तारिक रहमान की मलेशिया यात्रा को केवल एक सामान्य विदेश दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे साफ रणनीतिक सोच दिखाई दे रही है। बांग्लादेश नहीं चाहता था कि नई सरकार की पहली विदेश यात्रा सीधे भारत या चीन में से किसी एक देश की तरफ झुकाव का संकेत दे। यही वजह है कि ढाका ने मलेशिया को पहले पड़ाव के तौर पर चुना, ताकि वह खुद को तटस्थ दिखा सके और भारत, चीन प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाने का संदेश दे सके। लेकिन इसके राजनीतिक और सामरिक मायने काफी बड़े हैं। मलेशिया यात्रा के बाद चीन जाने की तैयारी यह संकेत देती है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को नए संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इससे भारत की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ढाका अब एक साथ चीन, तुर्किये, पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। यह आने वाले समय में भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती को और कठिन बना सकता है।

देखा जाये तो भारत के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। पाकिस्तान के साथ तुर्किये की साझेदारी पहले ही चिंता का कारण थी, लेकिन अब यदि बांग्लादेश भी उसी धुरी का हिस्सा बनने लगता है, तो यह भारत की पूर्वी सुरक्षा संरचना के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत को कम करके आंकना ढाका, इस्लामाबाद और अंकारा तीनों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। भले ही बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान और तुर्किये के साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की कोशिश करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति बेहद दूरदर्शी और बहुस्तरीय मानी जाती है। कभी कभार ऐसा लग सकता है कि भारत चुप क्यों है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सही समय आने पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब बेहद सटीक और ताकतवर होता है। कूटनीति का जवाब कूटनीति से और रणनीतिक चालों का जवाब उससे भी बड़ी चाल से देना ही मोदी की कार्यशैली रही है। यही वजह है कि आज भारत केवल अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि उनके हर कदम का जवाब देने के लिए समानांतर रणनीतिक मोर्चे भी तैयार कर रहा है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

धृष्टद्युम्न और द्रौपदी

इस प्रकार राजा द्रुपद के पुत्रेष्टि यज्ञ में गर्भाधायक हविष्य के तैयार हो जाने पर द्रुपद पत्नी का ऋतुमती हो जाने के कारण यज्ञशाला से बाहिर चले जाना और मुहूर्त टल जाने के खयाल से किया धरा सब यज्ञ व्यर्थ जाता देखकर ऋत्विजों द्वारा उस हविष्य का अग्निकुण्ड में ही स्वाहा कर देना, एवं उस अग्निकुण्ड में से धृष्टद्युम्न नामक कुमार और द्रौपदी नामक कन्या का प्रादुर्भूत होना, वेद मन्त्रों की अलौकिक शक्ति का चमत्कार ही समझना चाहिए।

मत्स्यगन्धा और मत्स्यराज

उपरिचर राजा द्वारा अपनी ऋतुस्नाता पत्नी के पास सधाये हुये बाज नामक पछी द्वारा वीर्य्य भेजने पर मार्ग में अन्य पक्षियों के झमेले में वीय्यं का दौना गिर-जाना और वीर्य्य का शापवश मछली बनी हुई अद्रिका नामक अप्सरा के अन्दर चले जाना जिससे मत्स्य नामक कुमार और मत्स्यगन्धा नामक कन्या का प्रादुर्भूत होना भी अमोध वीर्य्य की महिमा का ही अन्यतम उदाहरण समझना वाहिए

हम मन्त्रमहिमा ओर अमोघ वीर्य्य का रहस्य पीछे लिख आये हैं अत: यहाँ पुन: चर्वितचर्वण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

गोकर्ण जन्म

पद्म-पुराणान्तर्गत-श्रीमद्भागवत माहात्म्य में वर्णन आता है कि आत्माराम नामक नि:संतान ब्राह्मण को एक महात्मा ने गर्भाधायक ने फल देकर उसके विधिपूर्वक खाने की व्यवस्था की। परन्तु पण्डिताइन जी अजीव ढंग की औरत थीं, अत: उन्होंने वह फल स्वयं न खाकर अपनी गाय को खिला दिया, जिससे यथा समय गाय के पेट से मनुष्याकृति किन्तु गाय के सदृश कानों वाला बच्चा पैदा हुआ। वह अपनी अवस्था में जाकर अत्यन्त विद्वान् एवं धार्मिक मनुष्य प्रसिद्ध हुआ।

क्रमशः ...

आदिवासी स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस 9 जून को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में 'धरती आबा' (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया।

स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से धरती आबा कहने लगे।

उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिकु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात- अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)।

कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में, चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में, 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था।

विदेश मंत्री रूबियों देश के नेताओं को दिखा गए आईना

योगेंद्र योगी

भारत दौर पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। हम इन्हें गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी बेवकूफ लोग मौजूद हैं। %क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग% (क्वाड) की बैठक में शिरकत करने राजधानी दिल्ली में आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अमरीका में भारतीयों पर नस्लीय हमलों को लेकर यह जवाब दिया।

रुबियो ने कहा कि मैं नस्लभेदी कमेंट्स को बहुत गंभीरता से लूंगा। मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर कमेंट्स किए हैं, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग मौजूद होते हैं। मुझे यकीन है कि यहां भी बेवकूफ लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बेवकूफ लोग हैं जो हर समय बेवकूफी भरे कमेंट्स करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत ही वेलकमिंग देश है। दुनिया भर से हमारे देश में आने वाले लोगों से फायदा हुआ है।

अमरीकी विदेश मंत्री को शायद अंदाजा होगा कि नस्लवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद भारत के अभिन्न अंग हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक करके देश को कमजोर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में भारत के राजनीतिक दल ही सबसे आगे हैं। इसमें चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कोई भी अपने राजनीतिक स्वार्थों को भुनाने में पीछे नहीं रहता। सत्ता में जो भी राजनीतिक दल होता है, वह यंत्रणा और क्रूरता को कानूनी आड़ में जायज ठहराने का प्रयास करता है। इसका देश में सबसे बड़ा उदाहरण है पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें।

अमरीका में एक अश्वेत युवक की पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी थी। इससे पूरे अमरीका में बवाल मच गया था। 25 मई 2020 को मिनियापोलिस शहर में %डेरेक शॉविन% नामक एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के निहत्थे अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर लगभग 9 मिनट तक अपना घुटना दबाए रखा था, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के तहत अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुए। आरोपी पुलिस अधिकारी को हत्या का दोषी ठहराया गया और 2021 में उसे 22.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई।

इसके विपरीत भारत में पुलिस हिरासत में मौतें साधारण घटनाओं में शुमार है। सरकारी तंत्र को ऐसी मौतों से खास फर्क नहीं पड़ता। सरकार ऐसी मौतों को कभी गंभीरता से नहीं लेती। कारण साफ है ऐसी मौतों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर सत्ततंत्र जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि हिरासत में मौतों जैसे बेहद अमानवीय और संवदेनशील मुद्दे पर भी सरकारें खामोश रहती हैं। विपक्ष जरूर कुछ शोर मचाता है, किन्तु विपक्ष जब सत्ता में रहा होता है, तब भी ऐसी मौतें होती रही हैं, इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा गढ़े मुर्दे उखाड़े जाने के भय विपक्ष प्रायः चुप्पी ही साधे रहता है।

अदालतों ने भारत में पुलिस हिरासत में मौतें रोकने के प्रयास किए हैं, किन्तु सफल नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली हिंसा को व्यवस्था पर धब्बा बताया था। ऐसी मौतों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकतीं। शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी की थी।

हिरासत में मौतों पर अपवादस्वरूप ही दोषी पुलिसकर्मियों को अदालतों से सजा मिल पाती है। अप्रैल 2026 में, एक ऐतिहासिक और दुर्लभतम फैसले में मदुरै की एक अदालत ने वर्ष 2020 में पुलिस हिरासत में एक पिता (पी. जयराज) और पुत्र (जे. बेनिक्स) की बेरहमी से हत्या करने के मामले में 9 पुलिसकर्मियों को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई। जबकि अधिकतर मामलों में सबूतों के अभाव या गवाहों के मुकरने के कारण पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराना मुश्किल होता है, जिसके चलते कई मामलों में पुलिसकर्मियों को केवल विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है या वे बरी हो जाते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार वर्ष 2024 में 2,739 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। हिरासत में यातना सत्ता तंत्र की शक्ति और संवैधानिक मूल्यों का घोर दुरुपयोग है। ऐसा इसलिए, क्योंकि हिरासत में रखे गए लोग कमजोर और

असुरक्षित स्थिति में होते हैं और वहाँ शक्ति का संतुलन भी उनके खिलाफ होता है। जवाबदेही तय करने की स्वतंत्र जांच नहीं हो पाती है, क्योंकि हिरासत में हुई मौतों की जांच अक्सर उसी पुलिस विभाग द्वारा की जाती है, जिनके संरक्षण में ऐसी घटना घटित होती है। यातना के उपयोग को पुलिस बल के भीतर हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने से जोड़ा गया है।

भारत में यातना (टॉर्चर) को रोकने या उससे निपटने के लिए अब तक कोई विशेष, स्वतंत्र कानून नहीं बन पाया है। यद्यपि भारत ने 1997 में %संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन% पर हस्ताक्षर किए थे,लेकिन वर्तमान में यातना से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय संविधान के प्रावधानों का ही उपयोग किया जाता है। यातना निवारण विधेयक 2010 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की पुष्टि करना और यातना को स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध बनाना था। हालाँकि, प्रवर समिति को भेजे जाने और संशोधनों की सिफारिशों के बाद, यह विधेयक लैप्स हो गया और कानून का रूप नहीं ले सका।

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि भारत में हर साल सैकड़ों लोग हिरासत में मारे जाते हैं। उनका कहना है कि संदिग्धों से जबरन कबूलनामा निकलवाने के लिए यातना और दुर्व्यवहार करना पुलिसिंग का हिस्सा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के कई विशेषज्ञों ने भारत से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार करने का आह्वान किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हिरासत में मौतों को लेकर देश की सरकारों को खास फर्क नहीं पड़ता, तब अमरीकी विदेश मंत्री को अमरीका में मौजूद मामूली से नस्लवाद को लेकर शर्मिंदा होना देश के नेताओं को आईना दिखाने जैसा है।

आज का इतिहास

1720 स्वीडन और डेनमार्क ने स्टॉकहोम की तीसरी संधि पर हस्ताक्षर किये।
1732 जेम्स ओलेथोर्पे को सवाना और अल्तमहा नदियों के बीच प्रांतो जॉर्जिया के लिए एक शाही चार्टर प्रदान किया गया था।
1752 फ्रेंच सेना त्रिचीपॉली में ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण किया।
1772 नेविगेशन अधिनियमों के खिलाफ अवहेलना के एक मामले में, अब्राहम व्हिपल के नेतृत्व में अमेरिकनपात्रियोट्स ने ब्रिटिश स्कूनरगैनी पर हमला किया और जला दिया।
1790 वेल्स में मिलफोर्ड हेवन के बंदरगाह की स्थापना के लिए रॉयल सहमति दी गई।
1807 पोर्टलैंड के ड्यूक ने यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव जीता।
1815 लग्जमबर्ग फ्रांस के कब्जे से आजाद हुआ।
1815 नेपोलियन की हार के बाद वियना की कांग्रेस ने राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया।
1833 दुबई को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली।
1851 सतर्कता रूपों की एस एफ समिति (पहली बार) स्थापित की गयी।
1856 मॉर्मन के अग्रदूतों ने आयोवा सिटी, आयोवा को छोड़ना शुरू कर दिया, और पश्चिम की ओर जाने वाले साल्ट लेक सिटी, उटाह को छोड़ दिया, जहां वे दो पहिया वाहनों में अपनी सारी संपत्ति ले गए।
1862 अमेरिकी सिविल वॉर-कन्फेडरेट जनरल स्टोनवेल जैक्सन ने पोर्ट रिपब्लिक की एक लड़ाई इंतेहाई लड़ाई के साथ अपने सफल शेनडोना घाटी अभियान का समापन किया।
1863 अमेरिकी गृह युद्ध-यू.हिस्टोर में सबसे बड़ी घुड़सवार सगाई में, यूनियन और कन्फेडरेट बलों ने बैरंडी स्टेशन की लड़ाई में एक ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी।
1873 लंदन में एलेक्जेंड्रा पैलेस को इसके खोलने के बाद केवल एक पखवाड़े के बाद आग से नष्ट कर दिया गया।
1910 जापान और रूस ने पूर्व क्षेत्र के विभाजन पर एक समझौते किया।
1923 बुल्गारियाई सशस्त्र बलों ने अलेक्जेंडर स्टैंबोलीस्की की अध्यक्षता वाली बल्गेरियाई एग्रेरियन नेशनल यूनियन की सरकार को उखाड़ फेंका और इसकी जगह अलेक्जेंडार त्सानकोव को दिया।
1930 शिकागो बोर्ड ऑफ़ ट्रेड बिल्डिंग को खोला गया।
1931 डोनाल्ड डक कार्टून को पहली बार प्रदर्शित किया गया।
1940 नार्वे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

महज एक माह में तृणमूल कांग्रेस के तिनका-तिनका बिखरने के मायने...

अजय बोकिल

पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी अ.भा.तृणमूल कांग्रेस को राज्य में विधानसभा चुनाव हारे महज महीना ही हुआ है, लेकिन इन तीस दिनों में पार्टी जिस तरह तिनका-तिनका बिखर रही है, वह अपने आप में हैरतनाक और राजनीतिशास्त्र के विद्यार्थी के लिए शोध का विषय है।

चुनाव हारने के बाद राजनीतिक पार्टियां कई बार टूटती-बिखरती हैं, लेकिन उसमें भी समय लगता है। लेकिन एक माह पहले तक 'अजेय' समझी जाने वाली टीएमसी के विधायक दो फाड़ हो गए और सांसद कभी भी दो हिस्सों में बंट सकते हैं। टूटन का यह खेल निचले स्तर तक भी पहुंच चुका है।

टीएमसी में बिखराव के इस खेल के पीछे भाजपा का हाथ माना जा रहा है, लेकिन भाजपा तो निमित्त है, जो हो रहा है, उससे यह भी उजागर हो रहा है कि टीएमसी वैचारिक, संगठनात्मक और प्रतिबद्धता की दृष्टि से कितनी पोली जमीन पर खड़ी थी। कभी राजनीतिक विचार क्रांति के केन्द्र रहे बंगाल में सियासत का मतलब अब केवल सत्ता का गोंद है, यह टीएमसी के हश्र से सिद्ध हो रहा है।

ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं- कल तक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की नेता बनने का ख्वाब देख रही ममता बैनर्जी क्या बंगाल में ही अपनी पार्टी को बचा पाएंगी? क्या हर क्षेत्रीय अथवा जातिवादी पार्टी की त्रासदी परिवारवाद ही है? ममता की पार्टी के राजनीतिक अवसान से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नए सिरे उभार को मदद मिलेगी या कांग्रेस भी अंततः इसी अंतर्विरोध का शिकार होगी? और यह भी कि भाजपा का 'बंगाल मॉडल' देश के राजनीतिक नक्शे और तासीर को कितना और कैसे बदलेगा?

ममता बनर्जी जितनी जुझारू हैं, उससे भी ज्यादा झगड़ालू नेता हैं। हर वक्त पंगा और टकराव तालियां तो बजवा सकता है, लेकिन जनता के मन में एक गंभीर और विश्वसनीय नेता की छवि निर्मित नहीं कर सकता। अगर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ही बात की जाए तो उसकी विचारधारा में अल्पसंख्यकों की ओर झुकी हुई धर्मनिरपेक्षता, बंगाली भाषा और अस्मिता का आग्रह तथा रेवड़ी और कल्याणकारी सरकार के साथ देश के सर्वांगीण विकास का आग्रह है, लेकिन बुनियादी तौर पर वह सत्ता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के गणित से ही संचालित होता है।

ममता उद्योगों के लिए लोगों की जमीनों के हस्तांतरण और तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार का तगड़ा विरोध कर 2011 में सत्ता में आईं। लेकिन बंगाल में सत्ता में जमे रहने के राजनीतिक अनुष्ठान के अलावा और कुछ नहीं हुआ। परिणामस्वरूप लोगों को ममता राज से मोहभंग होने लगा और उन्हें एक सशक्त विकल्प की तलाश थी, जो 2026 के चुनाव में भाजपा के रूप में मिला और मतदाता से उसे ही जिता दिया।

अब भले ही ममता इसका ठीकरा एसआईआर और भाजपा की साम्प्रदायिकता पर फोड़ती रहें, लेकिन सच सामने आ रहा है। ममता सरकार कुशासन के प्रति लोगों का

गुस्सा उन्हें सत्ता से बेदखल करने के बाद भी थमता नहीं दिख रहा। लेकिन पार्टी में भी बगावत का सिलसिला अगर नहीं थम रहा तो इसका बड़ा कारण ममता बनर्जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया और परिवारप्रेम है।

यही वो फांस है, जिसकी लगभग सभी क्षेत्रीय और जातिवादी पार्टियां शिकार हैं, यह जानते हुए भी कि यह प्रवृत्ति अततः उनके पतन का कारण बनती है। यह बात अलग है कि ऐसे नेता दीवार पर लिखी इस इबारत को नहीं पढ़ना चाहते। ममता की पार्टी में टूटन का अभिषेक भतीजे अभिषेक बनर्जी को 2021 से अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिशों से हो गया था। आम कार्यकर्ता में यही संदेश गया कि उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।

अभिषेक ने भी पार्टी को तानाशाह की तरह से चलाना शुरू किया। जबकि ममता ने पार्टी में बढ़ रही आंतरिक नाराजी और कुलबुलाहट को लगातार अनदेखा किया। उसका नतीजा इस विधानसभा चुनाव में आ गया। यदि वो बीमारी का सही वक्त पर इलाज कर लेतीं तो शायद पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे अलग भी हो सकते थे।

सबसे आश्चर्य की बात उन मुस्लिम विधायकों का भी ममता का साथ छोड़ जाना है, जिनके लिए ममता ने तुष्टिकरण का इल्जाम अपने सिर पर लिया और ये वोट बैंक अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। टीएमसी के टिकट पर जीते 17 मुस्लिम विधायक अब बागी गुट के साथ हैं।

जिन 58 बागियों की अगुवाई कर ऋतुब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विस में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, वो खुद पुराने कम्युनिस्ट हैं और सीपीएम से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि ऋतुब्रत पर लगे चारित्रिक आरोपों के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था। उसके बाद ऋतुब्रत टीएमसी में आ गए और ममता दीदी के चहेते बन गए। लेकिन हम उम्र अभिषेक को ज्यादा तवज्जो मिलने के बाद उन्होंने बगावत का रास्ता चुन लिया।

यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह 2011 के विस चुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर राज्य में बरसों से जमे कम्युनिस्टों को हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल कर दिया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता ने टीएमसी विधायक दल को तोड़कर उस पुरानी पराजय का अपने ढंग से बदला ले लिया है।

अब सवाल ये कि क्या ममता अपने पार्टी की इमारत को फिर पहले की तरह मजबूत शक्ल में खड़ी कर पाएंगी, खासकर तब कि जब टूटन निचले स्तर तक पहुंच गई हो? इसका जवाब न में ज्यादा है, क्योंकि एक तो ममता की बढ़ती उम्र और दूसरे, भतीजामोह से उनका न उबर पाना। वैसे भी आने वाले पांच बरसों में भाजपा राज्य में हर स्तर पर पांव जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

तीसरे, बांगलादेश में युनूस सरकार के समय जिस तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार हुए, उस पर ममता के मौन से बंगाली हिंदू भी आक्रोशित हुए और बंगाली अस्मिता पर शायद पहली बार हिंदुत्ववादी सोच इस तरह हावी हुआ। इसे बदलना अब आसान नहीं है। ऐसे में अब टीएमसी के साथ वो ही लोग रहेंगे, जो ममता के भक्त हैं। यानी टीमएसी रहेगी तो लेकिन विपक्ष की सीमित भूमिका में। बाकी सत्ता के साथ जाएंगे।

टीएमसी के पतन का राज्य में कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा या कम्युनिस्टों को फिर संजीवनी मिलेगी, इस बारे में कोई भी कथन जल्दबाजी होगा। इतना तय है कि कांग्रेस अब ममता को ज्यादा भाव नहीं देगी। आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे में भी वह ज्यादा दबंगई से सौदेबाजी कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके विपक्ष का नेतृत्व करने की संभावना पर भी पानी फिर गया है। यानी विपक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथों में ही रहेगी। राज्य में वामपंथियों की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। लेकिन पहले सी व्यापक स्वीकृति अब मुश्किल है।

यहां सबसे दिलचस्प बात भाजपा का 'पश्चिम बंगाल मॉडल' है। इस राज्य में विस चुनाव के पहले इसी स्तम्भ में मैंने लिखा था कि चुनाव नतीजे जो भी हों, भाजपा का बंगाल मॉडल एकदम नया होगा। वही हो भी रहा है। कुछ लोग इसे सत्ता प्राप्ति के 'महाराष्ट्र मॉडल' से जोड़ कर देख रहे थे, लेकिन वह सही नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा ने दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को राज्य में सत्ता में पाने के लिए तोड़ा था, लेकिन बंगाल में चूंकि उसके पास पहले ही प्रचंड बहुमत है, इसलिए टीएमसी को तोड़ने के पीछे असली मकसद संसद में ताकत बढ़ाना है न कि राज्य में। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला अंदाज है।

माना जा रहा है कि विधायकों के टूटने के बाद जल्द ही टीएमसी के 29 लोकसभा सांसद भी दो फाड़ हो सकते हैं। अगर 20 सांसद भी अलग हुए तो वो पृथक गुट बनाकर भाजपा में विलय कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो लोकसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या 240 से बढ़कर 260 तक जा पहुंचेगी। बाकी 12 का इंतजाम भी किसी और तिकड़म से किया जा सकता है। और पार्टी अपने दम पर ही बहुमत में आ सकती है, जिसे अभी अपने एनडीए सहयोगियों के भरोसे सरकार चलानी पड़ रही है।

इस सारे खटकरम पर नैतिक सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन चूंकि भाजपा वैचारिक आवरण में व्यावहारिक राजनीतिक करती है। इसलिए वो साधन से ज्यादा साध्य को महत्व देती है। पश्चिम बंगाल से अब भाजपा को उखाड़ने के लिए किसी नए 'राजनीतिक अवतार' की जरूरत होगी, वो कब, कैसे जन्म लेगा, यह भविष्य की बात है।

अन्नामलाई की नई पार्टी इधु नम्मा इयक्कम के राजनीतिक मायने

सौरभ वार्ष्णेय

भाजपा प्रदेश पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा देकर एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की है यानी अपनी नई पार्टी का शुरुआज कर दी है जिसका नाम उन्होंने इधु नम्मा इयक्कम रखा है जिसका शाब्दिक अर्थ है यह हमारा आंदोलन है या यह हमारा जन-आंदोलन है । तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। तमिलनाडु इस समय बडे ऊहापोह की स्थिति से गुजर रहा है। भाजपा के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भाजपा से इस्तीफा देकर एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसे विभिन्न रिपोर्टों में वी द लीडर्स तथा तमिल पहचान आधारित नए जनआंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्नामलाई ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यह आंदोलन आगे चलकर एक पूर्ण राजनीतिक दल का रूप ले सकता है और भविष्य के विधानसभा चुनावों में भागीदारी करेगा। अन्नामलाई पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में भाजपा का सबसे चर्चित चेहरा बनकर उभरे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी होने के कारण उनकी छवि एक ईमानदार, आक्रामक और जमीनी नेता की रही है। भाजपा छोड़कर अलग राजनीतिक राह चुनना केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए विकल्प की तलाश का संकेत माना जा रहा है। उनका दावा है कि तमिलनाडु को वंशवाद, व्यक्तिपूजा और पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने नए आंदोलन की शुरुआत की है। के अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु भाजपा में कई नेताओं के त्यागपत्र सामने आए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास व्यक्तिगत समर्थन का एक मजबूत आधार मौजूद है। यदि यह समर्थन संगठित राजनीतिक शक्ति में बदलता है, तो भाजपा को राज्य में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं।हालांकि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन है, फिर भी तमिलनाडु जैसे राज्य में करिश्माई क्षेत्रीय नेतृत्व का अलग महत्व होता है। अन्नामलाई का बाहर जाना पार्टी के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ मुनेत्र कडग़म औरऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म के इर्द-गिर्द घूमती रही है। हाल के वर्षों में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजग़म ने भी नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दिया है। ऐसे में अन्नामलाई का नया मंच राज्य में तीसरे या चौथे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश करेगा। लेकिन केवल लोकप्रियता से राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। मजबूत संगठन, वित्तीय संसाधन, स्थानीय नेतृत्व और स्पष्ट वैचारिक दिशा किसी भी नई पार्टी की सफलता के लिए आवश्यक हैं। अन्नामलाई को इन सभी मोर्चों पर स्वयं को साबित करना होगा।

क्या नव-द्रविड़ राजनीति के सूत्रधार बनेंगे विजय

आर. राजगोपालन

सी विजय जोसेफ ने तमिलनाडु में एक ऐसी विचारधारा की शुरुआत की है, जिसे कई विश्लेषक %नव-द्रविड़ विचारधारा% बताते हैं। सौ साल पुरानी द्रविड़ अवधारणा इस समय संकट में है। महज 27 महीने पुरानी पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) ने उन दो दिग्गज पार्टियों (द्रमुक और अन्नाद्रमुक) के राजनीतिक वर्चस्व को खत्म कर दिया है, जो पिछले 72 वर्षों से तमिलनाडु पर राज कर रही थीं। विजय ने यह कमाल जेन-जी (जेनरेशन जेड) की द्रमुक-विरोधी भावना और राजशाही जैसे शासन के प्रति उनके विरोध का फायदा उठाकर किया। क्या द्रमुक की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले उदयनिधि स्टालिन, विजय की 'सुनामी' और 'नव-द्रविड़ युग' का मुकाबला कर पाएंगे?

आने वाले 10 से 15 वर्षों में, टीवीके के तमिलनाडु की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने की संभावना है। विजय द्रमुक, अन्नाद्रमुक, और जिला-स्तर की जाति-आधारित पार्टियों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। पूर्व भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने एक अलग पार्टी बना ली है, जो उदयनिधि के अलावा, यह टीवीके के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर सकती है। विजय और टीवीके सीधे तौर पर द्रविड़ विचारधारा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि पांच नेताओं के नामों का सहारा लेकर अपनी राजनीति को आकार दे रहे हैं। ये नेता हैं—के. कामराज, ई.वी. रामासामी 'पेरियार', वेलू नाचियार, अंजलाई अम्माल और बी.आर. आंबेडकर। अक्तूबर 2024 में टीवीके को लॉन्च करते समय, विजय ने पार्टी की जाति-विरोधी और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी द्रविड़ राष्ट्रवाद को तमिल राष्ट्रवाद से

अलग नहीं करेगी।

फिल्म जगत के नेताओं ने पारंपरिक द्रविड़ मॉडल को कमजोर करने में खासा योगदान दिया है। यह इसका भी संकेत है कि कैसे द्रविड़ विचारधारा कई टुकड़ों में बंट गई। द्रविड़ आंदोलन के मूल संगठन से कई शाखाओं का जन्म हुआ—डीके, द्रमुक, अन्नाद्रमुक, एमडीएमके, डीएमडीके और एएमएमके। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों ने सफलतापूर्वक अपने प्रशंसक-वर्ग को राजनीतिक वोट-बैंक में बदल दिया और उन्हें कट्टर द्रविड़ अवधारणा से दूर ले गए। उन्होंने सामाजिक न्याय और आत्म-सम्मान की मशाल को जलाए रखकर यह सुनिश्चित किया कि वंचितों के लिए 69 प्रतिशत तक आरक्षण बना रहे। उन्होंने इस आंदोलन की दिशा भी बदल दी। नतीजतन कई बार, द्रविड़ आंदोलन अपने रास्ते से भटक भी गया।

1972 में, एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) ने यह साबित करके एक बड़ा मोड़ ला दिया कि एक द्रविड़ नेता भी ईश्वर का भक्त हो सकता है। उन्होंने 17 अक्तूबर, 1972 को अन्नाद्रमुक की शुरुआत की और 1977 में मुख्यमंत्री बने। फिर जयललिता फिल्मों से राजनीति में आईं और 1991 में मुख्यमंत्री बनीं। उनके उदय ने द्रविड़ राजनीति की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अपने करिश्मा से लगातार छह कार्यकालों तक राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखा। इसी बीच, एक और फिल्मी हस्ती, विजयकांत ने 2005 में डीएमडीके की शुरुआत की। उन्होंने कुछ हद तक द्रविड़ संस्कृति के क्षरण को रोकने का प्रयास किया।

अब, सी. विजय जोसेफ ने द्रविड़ राजनीति के सात दशकों के वर्चस्व को ललकारा है। विजय ने पेरियार और आंबेडकर की सामाजिक न्याय की विरासत की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, और %विजयवाद% का सूत्रपात किया है। टीवीके द्वारा ब्राह्मणों को जगह देना एक अहम बदलाव है। लगता है कि विजय ने जयललिता से प्रेरणा ली है, जिन्होंने सफलतापूर्वक एक द्रविड़ पार्टी का नेतृत्व किया था। उन्होंने ब्राह्मणों को मंत्री पद दिया है, जिसमें संवेदनशील 'हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती' विभाग भी शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने आठ दलितों को भी महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपे हैं। पिछले दो दशकों में, द्रविड़ मूल के अस्तित्व की चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और अन्य तकनीकी बदलावों ने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी तरह बदल दिया है। तमिलनाडु अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां 'जेन-जी' राजनीतिक विमर्श को तेजी से प्रभावित कर रहा है-भले ही यह बदलाव बेहतर के लिए हो या बदतर के लिए।

1972 और 1989 के राजनीतिक घटनाक्रमों की एक समानांतर स्थिति अब 2026 में देखने को मिल सकती है। आज कोई ऐसा कद्दावर नेता नजर नहीं आता, जो विभिन्न द्रविड़ गुटों को एक ही बैनर तले एकजुट कर सके और पेरियार की विरासत को और अधिक धूमिल होने से रोक सके। डिजिटलीकरण, जेन-जी की आकांक्षाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आकर्षण, युवा पीढ़ियों को पारंपरिक वैचारिक आंदोलनों से धीरे-धीरे दूर खींच रहा है।

परीक्षा विवादों के चक्रव्यूह में घिरे धर्मेंद्र

आदिति फडणीस

शिक्षा मंत्रालय अपने आप में किसी विशाल साम्राज्य से कम नहीं है। स्वायत्त कहलाने वाला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शिक्षा मंत्रालय की निगरानी में काम करता है। सीबीएसई के तहत 26 देशों में 25,000 से अधिक स्कूल और 40 लाख छात्र (कक्षा 10वीं और 12वीं) आते हैं। उच्च शिक्षा विभाग 57 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, कुल 49,565 संबद्ध महाविद्यालयों, राज्यों के स्तर पर 537 निजी और 437 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों का संचालन करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों सहित इन उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2021-22 तक कुल लगभग 4 करोड़ छात्रों ने दाखिला लिया था। शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) इन संस्थानों के लिए कई परीक्षाएं आयोजित करती है। यह सब मंत्रालय की जिम्मेदारियों का महज एक छोटा सा हिस्सा है। इन सभी पर निगरानी रखने का दायित्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर है।

ऐसा नहीं है कि पहले अन्य मंत्रियों और सरकारों के कार्यकाल में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए मगर महज दो महीनों के भीतर ही राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या नीट-यूजी के कई प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। कक्षा 12 के अंक पत्रों में अशुद्धियां पाई गई हैं। संभवत: डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था जल्दबाजी में अपनाने के कारण ऐसा हुआ होगा।

खैर, कारण जो भी मगर मूल्यांकन प्रणाली पर छात्रों का विश्वास पूरी तरह डगमगा गया है। पुनर्मूल्यांकन की मांग ने सीबीएसई को अराजकता की स्थिति में धकेल दिया है। स्थिति की गंभीरता इस बात से और भी बढ़ जाती है कि कुछ ही सप्ताह में कॉलेजों में दाखिला शुरू हो जाएगा। सरकार ने शीर्ष अधिकारियों को बर्खास्त कर इन घटनाक्रम को गंभीरता से लेने के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि 'मंत्री प्रधान' को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान वाकई मुश्किल में

हैं? या उनके मंत्रालयों में मुसीबतें लगातार उनका पीछा? करती रही हैं?

वह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यभार संभालने वाले पेट्रोलियम मंत्री रहे हैं। प्रधान ने स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री के साथ शुरुआत की थी और फिर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का कारोबार में कोई दखल नहीं होना चाहिए और उन्होंने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण की दिशा में पहल की। इसके तहत कंपनी में सरकार की अपनी 52.9 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना था।

वर्ष 2020 में उन्होंने पत्रकारों से कहा,'बीपीसीएल में निजी निवेशकों की काफी दिलचस्पी है।' मगर यह योजना कभी कारगर नहीं हो पाई। वर्ष 2022 में केवल एक ही बोलीदाता बचा जिसके बाद सरकार ने यह प्रक्रिया ही रद्द कर दी। प्रधान के बाद पेट्रोलियम मंत्री बने हरदीप पुरी ने किसी भी तेल कंपनी के निजीकरण से इनकार कर दिया है। जब एक सार्वजनिक मंच पर पुरी से निजीकरण के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे 'बकवास' बताया।

नोटबंदी के ठीक बाद वर्ष 2017 से वर्ष 2019 के बीच प्रधान को कौशल विकास मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यह वह दौर था जो रोजगार की उम्मीद रखने वालों के लिए बेहद मुश्किल गुजरा। इसके बाद कोविड महामारी आ गई।

इस महामारी ने हर तरफ कोहराम मचा दिया। मंत्रालय में कोई बड़ी उपलब्धि देखने को नहीं मिली। उन्हें वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वर्तमान में शिक्षण कर्मचारियों की कमी देखते हुए स्कूल इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे सीबीएसई के उस आदेश का पालन कैसे करें जिसमें बच्चों के लिए तीन भाषाएं (जिनमें दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए) पढ़ना अनिवार्य किया गया है। यह नीति (जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षाधीन है) जुलाई में लागू होनी है।

हालांकि, राजनीति में प्रधान को कहीं अधिक सफलता मिली है। वह मध्य ओडिशा के तालचेर से हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान राजनीति में सक्रिय थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने थे। धर्मेंद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता बने और पहले साल ही तालचेर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। हालांकि, एक युवा भाजपा कार्यकर्ता के लिए ओडिशा में काम करना कठिन था।

वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीजू पटनायक के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण भाजपा राज्य में सत्ताधारी दल पर हमला नहीं कर सकी। जो लोग भाजपा और बीजू जनता दल (बीजद) दोनों दलों के साथ संतुलन साध कर आगे बढ़े वे प्रधान जैसे जुझारू भाजपा नेता की तुलना में राजनीति में अधिक सफल रहे। उदाहरण के लिए अश्विनी वैष्णव को ही लें जिन्होंने अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और नवीन पटनायक के करीब होने के कारण वाजपेयी के साथ काम किया। उन्हें बाद में राज्य सभा सीट मिली और अब वह मोदी सरकार में एक महत्त्वपूर्ण मंत्री बन गए हैं। यह अलग बात है कि वह अब भी विपक्ष में मौजूद अपने पूर्व 'मार्गदर्शक' पर हमला करने से कतराते हैं। इसके उलट प्रधान ने भाजपा के लिए लंबे समय तक अथक परिश्रम किया। उन्होंने ओडिशा में पार्टी को मजबूत बनाया और पार्टी को सरकार में लाने में मदद की। ओडिशा विधान सभा में भाजपा विधायक भारी तादाद में उनके समर्थक हैं मगर वह मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। प्रधान कोई करिश्माई नेता या प्रभावशाली वक्ता नहीं हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी की जंतर मंतर पर पहली रैली

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हुए प्रदर्शन ने केवल राष्ट्रीय राजनीति में हलचल नहीं मचाई, बल्कि देश के सामाजिक और युवा विमर्श को भी नई दिशा दे दी है। एक नई नवेली पार्टी के पहले ही कार्यक्रम में जिस तरह युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी, उसने पारंपरिक राजनीति के लिए साफ संदेश दे दिया है कि जेन जी अब नए तरह की राजनीति और नए चेहरों की तलाश में है। जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रही। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही खामियों और नाकामियों को मुद्दा बनाया। युवाओं का आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में शिक्षा माफिया का प्रभाव बढ़ा है, कभी पेपर लीक तो कभी सिस्टम की लापरवाही के कारण छात्रों का भविष्य लगातार संकट में पड़ रहा है। प्रदर्शन में शामिल युवाओं का कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा मंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन अभियानों से जन्मी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने पहले ही जमीनी प्रदर्शन में इतनी बड़ी भीड़ कैसे जुटा ली? इससे यह संकेत भी मिला कि डिजिटल मंचों पर चलने वाले अभियान अब सड़कों पर भी असर दिखाने लगे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नई पार्टी की वास्तविक ताकत और भविष्य का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस की युवा इकाई अखिल भारतीय युवा कांग्रेस से समर्थन मांगा था, लेकिन युवा कांग्रेस ने इससे दूरी बनाकर रखने का फैसला किया। उधर, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं के आवासों के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रदर्शन के संबंध में भीड़ नियंत्रण और रोकथाम के उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके को प्रदर्शन की अनुमति प्रदान कर दी थी। उधर, अमेरिका से नई दिल्ली पहुंचे अभिजीत दिपके का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें प्रदर्शन स्थल के लिए रवाना किया गया। हवाई अड्डे से बाहर निकलते समय अभिजीत दिपके ने पत्रकारों से कहा कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि पांच छात्रों ने आत्महत्या की है। उन्होंने इस मुद्दे को युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताया। दिपके ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अपील की। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे अपने साथ किताब और तिरंगा लेकर आएं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में फूल लाने की भी अपील की ताकि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित बना रहे। उधर, जंतर मंतर पर मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य सौरव दास ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री अयोग्य साबित हुए हैं और उन्हें या तो स्वयं इस्तीफा देना चाहिए अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। सौरव दास ने कहा कि जवाबदेही और सहयोग की संस्कृति को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह युवाओं द्वारा चलाया जा रहा राजनीतिक आंदोलन है और प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे। हम आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी अपने आंदोलन को तेज किया है। पार्टी के आधिकारिक संदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के पूर्ण समर्थन के साथ जंतर मंतर पर सुबह दस बजे से प्रदर्शन शुरू किया गया। इस दौरान अभिजीत दिपके को डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की आत्मकथा हाथ में लिए देखा गया। उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता और मुख्य सदस्य आशुतोष रांका भी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के रूप में हुई थी। यह अभियान उस समय चर्चा में आया जब प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान फर्जी कानून डिग्री वाले कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस शुरू हुई और धीरे धीरे यह व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन के रूप में सामने आया।

... तो क्रैश हो जाएंगे सारे कंप्यूटर?

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हिसाब ठीक से न कर पाने की वजह से 2038 में दुनियाभर के कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे? यह दावा कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ने किया है। उनकी माने तो 19 जनवरी, 2038 को ग्रीनिच मान समय के मुताबिक सुबह 3 बजकर 14 मिनट और 7 सेकेंड पर सारे कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे। उनका अनुमान है कि एक जनवरी, 1970 के बाद से सेकेंड की संख्या कंप्यूटरों के अंदर स्टोर एक अहम अधिकतम संख्या को पार करेगी। कई कंप्यूटर कई तरह की गड़बड़ियों के शिकार हो सकते हैं। इस पर नये सिरे से बहस छिड़ गई है क्योंकि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर वैज्ञानिकों का कहना है कि 2038 में होने वाली यह घटना मिलेनियम बग से कम नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि सवाल यह भी है कि आज के कंप्यूटर 23 साल बाद कितने काम में रहेंगे। आम लोग भले ही कंप्यूटर को बहुत समर्थ मानते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि कंप्यूटर ही नंबरों का हिसाब न कर पाए? 4 जून, 1996 को यूरोपियन एजेंसी का बिना मानव रहित एरियन 5 रॉकेट, चार महंगे सेटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष की ओर रवाना हुआ था। लेकिन 39 सेकेंड के बाद ही रॉकेट में धमाका हुआ और वो आग में तब्दील हो गया। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हिसाब ठीक से न कर पाने की वजह से हुआ। विश्लेषकों की माने तो अगर 248 दिनों को सेकेंड के 100वें हिस्से में गिना जाए तो जो संख्या सामने आती है वो वही 2,147,483, 647 है।

बड़ी इलायची में समाए चमत्कारी गुण

बड़ी इलायची जहां खाने में स्वाद का काम करती है। वहीं यह हमें कई बीमारियों में निजात दिलाने में भी हमारी मदद करती है। खांसी जुकाम हो जाए तो बडी इलायची की चाय या काढा बना के पीने से ठंड से राहत मिलेगी। इलायची का प्रयोग हमारे शरीर कई बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। साथ ही बड़ी का प्रयोग करने से आपकी त्वचा में निखार भी आता है।

कॉपर के अधिक सेवन से अल्जाइमर का खतरा

मस्तिष्क को प्रोटीन को कम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिमेंशिया का कारण बनने वाले प्रोटीन को कम करने के लिए मस्तिष्क का संघर्ष। रेड मीट, शेल फिश और सब्जियां भोजन में तांबे के प्रमुख स्रोत। दिमाग के रक्षा करने वाले तंत्र में हस्तक्षेप करता है कॉपर। लंबे समय तक कॉपर का अधिक सेवन करने वाले अब सावधान हो जाए क्योंकि अमरीकी वैज्ञानिकों ने चूहों पर अपने प्रयोग के बाद ताज़ा शोध में यह जानकारी दी कि लंबे समय तक भोजन में कॉपर का अधिक सेवन अल्जाइमर बीमारी की वजह बन सकता है।

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने कहा कि कॉपर की अधिक मात्रा के कारण मस्तिष्क को उस प्रोटीन को कम करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जिसे डिमेंशिया का प्रमुख कारण माना जाता है। शोध के निष्कर्ष पर वैज्ञानिकों के बीच बहस जारी है क्योंकि कुछ अन्य शोधों का कहना है कि कॉपर वास्तव में मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। रेड मीट, शेल फिश और सब्जियां भोजन में तांबे के प्रमुख स्रोत हैं। कॉपर के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने चूहों पर शोध किया। इस टीम ने पाया कि कॉपर दिमाग के रक्षा करने वाले तंत्र में हस्तक्षेप करता है। जिन चूहों को पानी में घोलकर ज़्यादा कॉपर दिया गया। उनके दिमाग़ की रक्त वाहिनियों में कॉपर की मात्रा बढ़ गई और उनके दिमाग की सक्रियता प्रभावित हुई।

वैज्ञानिकों का कहना है कि दिमाग की झिल्ली के काम करने के तरीके पर असर पड़ा। इसके साथ-साथ चूहों के दिमाग का बीटा एम्लॉयड के उस प्रोटीन से छुटकारा पाना कठिन हो गया, जो डिमेंशिया का प्रमुख कारण है। एल्जाइमर सोसायटी के डॉक्टर डाउग ब्राउन कहते हैं, तांबा शरीर के लिए अहम खनिज है, लोगों को इस शोध को सावधानी के साथ लेना चाहिए और अपने खाने से तांबे को हटाना नहीं चाहिए

भूख लगने पर ही खाएं

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग भूख न होने पर भी कुछ न कुछ खाते रहते हैं, इस तरह से कुछ न कुछ खाने की आदत आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। में हुए एक रिसर्च में बताया गया है कि भूख न होने पर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के लिए स्नातक के 45 छात्रों को शामिल किया। इन छात्रों से सबसे पहले इनके भूख के स्तर की जानकारी ली गई। इसके बाद इन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दिया गया।

भोजन की नियमित खुराकें स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती हैं, इसे जानने के लिए रिसर्चर्स ने प्रतिभागियों द्वारा भोजन करने के बाद उनके रक्त शर्करा का स्तर मापा गया। रिसर्च में पाया कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के बाद रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि हुई।

मधुमेह से पीड़ित लोग स्वस्थ खान-पान और जीवन भर हेल्दी डाइट योजना पर अमल कर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। मधुमेह को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कदम उठाते हुए अभाव का कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। न ही आपको मिठाई को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत है। बल्कि जीवन भर हेल्दी डाइट लेना महत्वपूर्ण है। फाइबर से उच्च और शुगर और फैट में कम और दिल के लिए स्वस्थ आहार मधुमेह प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मधुमेह से पीड़ित लोग स्वस्थ खान-पान और दैनिक आहार योजना बनाकर ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं।

मधुमेह नियंत्रण के सुझाव

मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए आपको कुछ उपायों पर अमल करना होगा। इसके लिए आपको अपने आहार को छोटे भागों में विभाजित करना होगा। नियमित रूप से अपने सभी आहार को लेने कोशिश करें। इसके अलावा अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और फाइबर से परिपूर्ण खाने की कई आइटम को जोड़ने का प्रयास करें।

मिथक : मधुमेह होने पर चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है।

तथ्य: मधुमेह होने पर चीनी को बिल्कुल नहीं लेना यह हम सभी के दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ आहार योजना को ठीक से लागू करने पर आप अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। मिठाई को सीमा से दूर रखने की जरूरत नहीं है जब तक यह एक स्वस्थ भोजन योजना का हिस्सा है या व्यायाम के साथ जुड़ा हुआ है।

मिथक: हाई प्रोटीन आहार सबसे अच्छा होता है।

तथ्य: अध्ययन से पता चला है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन, विशेष रूप से पशु प्रोटीन, खाना इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बन सकता है। जो वास्तव में मधुमेह का एक महत्वपूर्ण कारक है। संतुलित आहार एक कुंजी है। एक स्वस्थ आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल होता है। हमारे शरीर को ठीक ढ़ंग से काम करने के लिए तीनों की जरूरत होती है।

मिथक: कार्बोहाइड्रेट में कटौती करें।

तथ्य: संतुलित आहार खाना सेहत की कुंजी होती है। सर्विंग का साइज और कार्बोहाइड्रेट का प्रकार विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता हैं। इसलिए होलग्रेन कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान दें क्योंकि यह फाइबर का अच्छा स्रोत होता हैं। आसानी से पच जाता है और रक्त में शुगर के स्तर को सही रखता है।

दूध का सेवन

दूध कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सही संयोजन होता है और यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दैनिक आहार में दूध के दो गिलास पीना एक अच्छा विकल्प है।

उच्च फाइबर सब्जियां

अपने आहार में उच्च फाइबर सब्जियां जैसे मटर, सेम, ब्रोकोली, पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। इसके अलावा दालें भी एक स्वस्थ विकल्प हैं और इसे आपके आहार का हिस्सा होना चाहिए।

उच्च फाइबर फल

फाइबर से भरपूर फल जैसे पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती और अमरूद का सेवन भी करना चाहिए। आम, केले और अंगूर में शुगर की उच्च मात्रा होने के कारण इन फलों को सेवन कम करना चाहिए।

मधुमेह रोगियों के लिए

सर्वश्रेष्ठ आहार योजना

कृत्रिम स्वीटनर का कम इस्तेमाल

कृत्रिम स्वीटनर मूल रूप से शुगर से मिलने वाली कैलोरी को कम करता है। इन गोलियों का सेवन एक दिन में 6 गोलियों से कम होना चाहिए क्योंकि ज्यादा लेने से इसके साइड इफेक्ट होने लगते है। हालांकि, संयम एक बेहतर तरीका से जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है अगर डॉक्टर और रोगी संयोजन के साथ काम करें।

अतिरिक्त वजन कम करें

यदि आप मोटे हैं, तो मधुमेह की रोकथाम वजन घटाने पर निर्भर हो सकती है। वजन का हर एक किलो कम करना आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकता हैं और आपके लिए आश्चर्यजनक हो सकता है। कम कार्बोहाइड्रेंट आहार और आहार योजना आपको वजन कम करने में मदद कर सकती हैं।

महत्वपूर्ण है विटामिन डी

हम में से ज्यादातर लोग विटामिन डी को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। लेकिन यह मधुमेह से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विटामिन डी के स्तर की जांच की जानी चाहिए। कम विटामिन डी मधुमेह का कारण भी हो सकता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप पड़ना है।

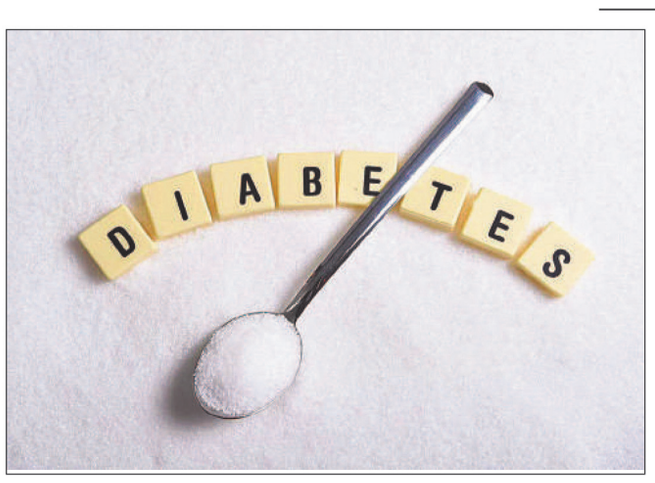

खाना पकाने की युक्तियां

मधुमेह रोगियों के लिए बिना तेल के खाना बनाना सीखना होगा। परिष्कृत उत्पाद (चीनी, सफेद आटा, सफेद चावल, फलों का रस आदि) खाना बंद करना होगा। साथ ही प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने बंद करने होगें। इसके अलावा डेयरी उत्पाद खाने और पीने बंद करने होगें।

मधुमेह रोगियों के लिए आहार योजना

सुबह जल्दी: 6-7 बादाम / 1-2 अखरोट।

नाश्ते में आइटम: 1 कटोरी ओट्स/ दूध/ 2 अंडे के स्लाइस/मल्टीग्रेन ब्रेड/सब्जियां/दही/टोस्ट।

सुबह का नाश्ता: आप पपीता, नारियल और छाछ आदि सहित मौसमी फल जोड़ सकते हैं।

दोपहर का भोजन: सलाद, सब्जियां, दाल, चपाती, दही, चावल, पनीर चिकन आदि।

शाम का नाश्ता: फल और स्नैक्स जैसे ढोकला, इडली, भुना हुआ नमकीन और मुरमुरा आदि।

रात का खाना: मिक्स्ट सब्जियों का सूप। चपाती, सब्जी, दाल/चिकन, हरा सलाद।

बच्चों पर साइबर बुलिंग का खतरा...

इंटरनेट के बिना आज हमारा जीवन अधूरा है और जहां तक आज के बच्चों का सवाल है, उनके लिए इंटरनेट के बिना दुनिया का कोई मतलब ही नहीं है। दुर्भाग्य से आमतौर पर माता-पिता अपने बच्चों की इंटरनेट गतिविधियों को लेकर अधिक जानकारी नहीं रखते हैं। वास्तविक दुनिया की तरह इंटरनेट की दुनिया में भी बच्चे कई तरह के खतरों के प्रति अनजान होते हैं। नार्टन ऑनलाइन फैमिली रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि 79 फीसदी बच्चे नकारात्मक ऑनलाइन स्थिति का सामना करते हैं और 60 फीसदी किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम के शिकार हैं। साइबर बुलिंग में गलत अफवाहों का फैलना, धमकी भरे संदेशों का प्रसार और अपमानजनक तस्वीरें पोस्ट किए जाना आदि शामिल हैं। साइबर बुलिंग करने वाला टेक्स मैसेज, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, सोशल नेटवर्किंग मैसेज भेजता है या ब्लॉग, वेब पेज पर या ऑनलाइन गेम प्लेटफार्म पर ऐसी सामग्री पोस्ट करता है, जो दूसरों को परेशान, अपमानित करने या डराने-धमकाने के लिए होती है। तकनीक का लाभ उठाकर वे ऐसे संदेश और सामग्री व्यापक रूप से प्रसारित करते हैं।

क्या हैं कारण?

साइबर बुलिंग के कारण अक्सर उसी तरह के होते हैं, जो आम तौर से स्कूल परिसरों में दी जाने वाली धौंस-धमकी के होते हैं। मसलन शक्ति का प्रदर्शन करना, बदला लेने की इच्छा या हुए नुकसानों की भरपाई। कोई पीड़ित जब अपना बचाव करने के लिए ऑनलाइन गलत संदेश का प्रसार करता है तो उसे भी साइबर बुलिंग के रूप में देखा जा सकता है। साइबर बुलिंग प्रायः गुमनाम

रहकर की जाती है और इसे बार-बार दोहराया जाता है। यह किसी एक व्यक्ति या ऑनलाइन ग्रुप का काम हो सकता है। दुर्भाग्य से अन्य नकारात्मक ऑनलाइन अनुभवों की तरह साइबर बुलिंग का भी बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है।

प्यार से लाएं राह पर

बच्चों के लिए इंटरनेट का अनुभव सुरक्षित बनाने के लिए उनके माता-पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। आधुनिक माता-पिता उस पहली पीढ़ी के माता-पिता हैं जिन्हें अपने बच्चों को न केवल वास्तविक दुनिया में बल्कि तेजी से विस्तृत होती आभासी दुनिया में भी सुरक्षित रखने के सभी उपाए करने होंगे।

नकारात्मक अनुभव: एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्वभर के लगभग 62 फीसद बच्चों ने प्रतिक्रिया दी कि ऑनलाइन होने के समय उन्होंने कोई नकारात्मक अनुभव प्राप्त किया। 10 में लगभग 4 के लिए हालांकि ऐसा ऑनलाइन नकारात्मक अनुभव अधिक गंभीर रहा, जैसे कि अजनबियों से कोई अनुचित तस्वीर प्राप्त करना, धमकाया जाना या साइबरक्राइम का शिकार हो जाना। आज प्रत्येक चार में एक भारतीय माता-पिता इस बात से चिंतित हैं कि उनके बच्चे को ऑनलाइन धमकाया जा सकता है।

कैसे बचाएं बच्चों को: बच्चों के साथ बेहतर संवाद कायम रखें। बच्चों के साथ तकनीक का सुरक्षित व समुचित उपयोग करने के महत्व के बारे में खुलकर बात करें। बच्चे की इंटरनेट गतिविधियों व सेलफोन इस्तेमाल पर निगाह रखें। देखी गई साइटों पर चर्चा करें और जरूरी हो तो कॉल लॉग भी ब्राउज करें। यदि बच्चे को ऐसा करना दखलंदाजी लगे तो अपने बच्चे की भलाई के लिए वास्तविक सरोकारों पर जोर दें। साइबर बुलिंग के संकेतों को पहचानें। अनेक लक्षण हैं जिन्हें लेकर सचेत रहें, मसलन फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, खासतौर से सेलफोन या कंप्यूटर उपयोग करने के बाद ऐसा बर्ताव करना, दोस्तों या रोजमर्रा की सामान्य मनोरंजक गतिविधियों से कट जाना या फिर स्कूल में बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन में किसी प्रकार की गिरावट दिखाई देना या अरूचि होना आदि।

सतर्कता जरूरी: ऑनलाइन पैरेंटिंग, वास्तविक जीवन में पैरेंटिंग से कोई अलग नहीं है। माता-पिता को केवल नियम नहीं बनाने हैं, उन्हें समझना होगा कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं और उनके बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर पूरी निगाह रखनी होगी। माता-पिता द्वारा बच्चों को इंटरनेट संबंधी ऐटिकेट की जानकारी देना, सामाजिक कौशल सिखाने के समान ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन किसी भी अप्रिय स्थिति से रूबरू होने पर भारतीय बच्चे, अपने माता-पिता को बताते हैं, वहीं अभिभावकों को इसके बदले में अपने बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने हैं।

रेसिपी

राजमा गलाउटी कबाब

सामग्री

3/4 कप सलाईस्ड प्याज, 2 टेबल-स्पून घी, 2 टेबल-स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 1 1/2 टी-स्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टी-स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 कप पनीर, 3/4 कप भिगोए , उबले और हलके मसले हुए राजमा, 1/2 कप उबले , छिले और मसले हुए आलू, 1 टेबल-स्पून कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वादअनुसार, 1/2 टी-स्पून गरम मसाला, 1 टेबल-स्पून तेल

विधि

कढ़ाई मे मध्यम आंच पर तेल गरम करें और प्याज़ डालकर उनके सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज़ पर निकालकर एक तरफ रख दें। पैन में घी गरम करें, अदरक और हरी मिर्च डालकर 30 सेकेन्ड तक भुन लें। तेल छोड़कर, बची हुई सामग्री डालकर 3-4 मिनट तक पका लें। मिश्रण को 5 बराबर भाग में बांट लें और प्रत्येक भाग के चपटे गोल कबाब बना लें। कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गरम कर लें और कबाब डालकर उनके सुनहरा होने तक तल लें। तेल सोखने वाले कागज़ पर निकालकर गरमा गरम परोसें।

सान्वा पान्की

सामग्री

2 कप सामा , पीसकर मुलायम पाउडर बना हुआ, 1/2 कप राजगीरे का आटा, 4 टेबल-स्पून आरारोट आटा, 2 टेबल-स्पून घी, 1 टी-स्पून ज़ीरा, 3/4 कप खट्टा दही , फेंटा हुआ, सेंधा नमक , स्वादअनुसार, 1 टेबल-स्पून बारीक कटा धनिया, 1 1/2 टी-स्पून अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, 4 से 6 केले के पत्ते, 150 मि.मी. चौकोर टुकड़ो में कटे हुए, चुपड़ने और पकाने के लिए तेल, **परोसने के लिए:** हरी चटनी, भावनगरी मिर्च

विधि

सामे का पाउडर, राजगीरे का आटा, अरारोट आटा, दही, सेंधा नमक, धनिया, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा और 1/2 कप पानी को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और मुलायम घोल बना लें। ढ़ककर खमीर उठने के लिए 1 घंटा एक तरफ रख दें। केले के पत्तों के एक तरफ को तेल से चुपड़े और एक जगह रख दें। 2 टेबल-स्पून घोल को केले के पत्ते के एक तरफ रखें और पतली परत में फैला लें। पत्ते की दुसरी तरफ को घोल के उपर रखें और मोड़ लें। एक नॉन-स्टिक पैन या तवा गरम करें और पान्की को थोड़े से तेल का प्रयोग कर दोनों तरफ से पान्की के पत्ते से अलग होने तक पका लें। बचे हुए घोल को प्रयोग कर 14 और पान्की बना लें। हरी चटनी और भावनगरी मिर्च के साथ तुरंत परोसें।

पुरुषों के लिए फिट रहने के टिप्स

फिटनेस की परिभाषा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नहीं होती है। बल्कि शारीरिक फिटनेस शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नियमित एक्सरसाइज से न केवल मांसपेशियों में ताकत आती है बल्कि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता हैं, ढलती उम्र धीमी पड़ जाती है और कई अन्य तरह के रोगों से बचाव होता है। इसलिए पुरुषों को फिट रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आरामफरामोश न बनें

आधुनिक और आराम तलब जीवनशैली के कारण पुरूष 20 साल के बाद ही हृदयघात के खतरों की चपेट में आने लगते हैं। जो लोग आराम तलब जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज करने से जी चुराते हैं और जंक व डिब्बा बंद आहार पर जीते

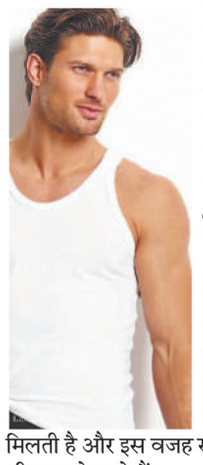

हैं उनमें खराब कोलेस्ट्रोल या निम्न घनत्व वाले लिपोप्रोटीन का स्तर रक्त में हमेशा उच्च रहता है। अपने शरीर में एलडीएल के स्तर को कम करने के लिए नियमित एक्सरसाइज करके एचडीएल के स्तर को उंचा उठाया जा सकता है।

रक्तचाप सामान्य रखें

जीवन में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण पैदा हुए निराशा और तनाव के कारण पुरूषों में उच्च रक्तचाप की बीमारी होना एक आम बात हो गई है। नियमित व्यायाम से रक्तचाप के स्तर को सामान्य रखने में मदद मिलती है और इस वजह से हृदयघात और हृदय रोगों के खतरे भी कम हो जाते हैं।

बढ़ाएं ब्लड सर्कुलेशन

जब आप एक्सारसाइज करते हैं तब शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और शरीर में ब्लड की सप्लाई भी अधिक होने लगती है। रक्त धमनी शरीर में ब्लड की जरूरत के अनुसार फैलता और सिकुड़ता रहता है। लेकिन जब अदमी आराम तलबी का जीवन जीने लगता है कोई श्रम या एक्सरसाइज नहीं करता हैं तब उसके रक्त धमनी में कोलेस्ट्रोल जमा होने से रक्त धमनी सिकुड़ जाती है जो अंततः हृदय घात का कारण बनती है।

बीमारियों के खतरे कम करें

अस्वस्थ जीवनशैली और खानपान में अनियमितता के कारण वर्तमान में डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, हृदय की बीमारियां, पेट की समस्याएं आदि बढ़ रही हैं। इन बीमारियों से बचाव की कोशिश कीजिए। इसके लिए रोज व्यायाम करें और नियमित जांच कराए।

वजन कम करें

वजन बढ़ने से कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं, इसलिए अपने वजन को नियंत्रण में रखें। वजन कम करने से दिल की बीमारियां नहीं होती हैं। इसलिए इसपर काबू पाने के लिए रोज व्यायाम करें और हेल्दी आहार का सेवन करें। पुरुष इन सामान्य सी बातों को ध्यान में रखकर न केवल फिट रह सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सहमति से बने संबंध चरित्र पर धब्बा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे निजी संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र के बारे में प्रतिकूल धारणा बनाना उचित नहीं है।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून दो अविवाहित वयस्कों को सहमति से संबंध बनाने से नहीं रोकता और ऐसे संबंधों को नैतिक पतन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मामला एक ऐसे उम्मीदवार से जुड़ा था, जिसका चयन पुलिस कांस्टेबल पद के लिए हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज एक पुराने आपराधिक मामले का हवाला देकर नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। भर्ती बोर्ड का तर्क था कि उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज मामला उसके नैतिक आचरण पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

हेमंत सोरेन को डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका को खारिज किया है, जिससे अब इस बहुचर्चित मामले में मुख्यमंत्री सोरेन सहित करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने का रास्ता साफ हुआ है। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो कि अब सुनाया गया है। सीएम सोरेन ने अपनी याचिका में खुद को निर्दोष बताकर मामले से आरोपमुक्त करने की मांग की थी। उनका मुख्य तर्क था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, और इसलिए उन्हें मामले से बरी किया जाएं। हालांकि, विशेष अदालत ने सोरेन की इन दलीलों को स्वीकार नहीं कर उनकी डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर ईडी के पक्ष को मजबूती प्रदान की।

14 टीएमसी सांसदों ने भाजपा नेताओं से की मुलाकात

नईदिल्ली। एक ओर जहां दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हो रही है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 14 सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। इस मुलाकात के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेन्दु शेखर रॉय के पार्टी से इस्तीफा देने के तुरंत बाद, नई दिल्ली में उनकी और टीएमसी के पांच लोकसभा सांसदों की मुलाकात ने नए राजनीतिक कयासों को जन्म दिया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पार्टी पहले से ही आंतरिक असंतोष की आशंकाओं से घिरी हुई है। राज्यसभा सांसद इस्तीफा देने के बाद, सुखेन्दु शेखर राय ने आरजी कर हत्याकांड और बलात्कार की घटना पर कहा, सत्ता का नशा उनके (टीएमसी के) सिर पर इस कदर चढ़ गया था कि उन्हें लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें छू भी नहीं सकता।

ईडी ने ड्रग्स नेटवर्क और करोड़ों की संपत्ति किया खुलासा

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम , 2002 की धारा 17 के तहत हुई है। ईडी की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगरतला जोनल यूनिट द्वारा हाल ही में जब्त की गई 49.101 किलोग्राम मेथामफेटामाइन और 40 ग्राम हेरोइन से जुड़े मामले से जुड़ी है। जांच एजेंसी की छापेमारी मिजोरम-म्यांमार और त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी की गई, जहाँ संबंधित ठिकाने सीमाओं से कुछ ही सौ मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। जांच में सामने आया है कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क म्यांमार से मेथामफेटामाइन को मिजोरम के चम्फाई/जोकॉथर सेक्टर के रास्ते भारत में लाता था। जिसे कई बैंक खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से ठिकाने लगाया गया था। यह एक संगठित सीमा-पार ड्रग सिंडिकेट है।

तेज आंधी से एअर इंडिया के तीन विमान ग्राउंड सपोर्ट उपकरण से टकराए, बड़ा हादसा टला

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज आंधी से एअर इंडिया के तीन विमान ग्राउंड सपोर्ट उपकरण से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। डीजीसीए इस हादसे की पूरी जांच करेगा और लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय करेगा। ये हादसा रविवार शाम एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर हुआ था। अचानक आई तेज आंधी और तूफान की वजह से वहां खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से हिल गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवाओं के थपेड़ों के कारण ये उपकरण वहां पार्क किए गए एयर इंडिया के तीन सिंगल आयल एयरक्राफ्ट से जा टकराए। इस टक्कर में तीनों विमानों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले की गहन जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। उस समय तूफान को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी।

इंडिया ब्लॉक मीटिंग में खरगे का चौतरफा हमला

विदेश नीति से एसआईआर तक मोदी सरकार को घेरा

नईदिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में गठबंधन की बैठक में इंडिया ब्लॉक के अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने देश के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति संबंधी चुनौतियों को उजागर किया और देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की आलोचना की। अपने शुरुआती संबोधन में, खर्गे ने संसद में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक को हराने में गठबंधन की एकता की सराहना की।

विभिन्न मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता ने महंगाई, परीक्षाओं में अनियमितताओं को उजागर किया और केंद्र में भाजपा सरकार को निशाना बनाने के लिए समझौतावादी विदेश नीति का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर खरगे की टिप्पणी साझा करते हुए कहा, इंडिया गुट के नेताओं की इस बैठक में आप सभी का स्वागत है। इस समूह का गठन लगभग ठीक तीन साल पहले हुआ था। मैं अधिक विस्तार से बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे सामने जो मुद्दे हैं, वे आप सभी को भलीभांति ज्ञात हैं। 17 अप्रैल, 2026 को हमने लोकसभा में अपनी एकता और एकजुटता का बेहद निर्णायक प्रदर्शन किया, जब हम सभी एक साथ मजबूती से खड़े हुए और मोदी सरकार के परिसीमन संबंधी दुर्भावनापूर्ण विधेयकों को पराजित किया।

खरगे ने आगे कहा कि अब हमें उसी भावना को मजबूत और आगे बढ़ाना होगा, ताकि हम मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने मौजूद कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकें। एसआईआर के कारण हमारे लाखों लोगों के मतदान अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का लगातार राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने, डराने-धमकाने और उन पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर-भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है।

इंडिया ब्लॉक के नेता आज मीडिया से मिलेंगे। नए रोजगार सृजित करने के लिए आवश्यक नए निवेश उस गति से नहीं हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहे हैं और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं

की आशाएं और आकांक्षाएं चकनाचूर हो रही हैं। समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में, के विरुद्ध अत्याचार बेरोकटोक जारी हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से कमजोर हो गई है और जिन पारंपरिक मूल्यों का भारत ने लंबे समय से दृढ़ता से समर्थन किया है, उन्हें कायम नहीं रखा गया है।

इंडिया ब्लॉक का एक ही लक्ष्य, विश्वासघातियों को सत्ता से बेदखल करेंगे : संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने सोमवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक का एकमात्र उद्देश्य देशद्रोह करने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। इंडिया ब्लॉक ने उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक की। एएनआई से बात करते हुए, राउत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव किया। ये पोस्टर नई दिल्ली के कई चौराहों पर इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले लगाए गए थे, जिनमें उन्हें निशाना बनाया गया था।

इन पोस्टरों में एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के वे बयान शामिल थे, जिनमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई थी। राउत ने कहा कि राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले मूर्ख हैं। वे देश के सबसे महत्वपूर्ण, लोकप्रिय और जोशीले नेता हैं। सरकार उनसे डरती है। हम आज इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग लेंगे, लेकिन वर्चुअल माध्यम से। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है- देश के साथ विश्वासघात करने वालों को सत्ता से हटाना।

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने 2029 के आम चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक के भीतर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को पेश करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि चाहे आम चुनाव हों या राज्यों में विधानसभा चुनाव, एक चेहरा होना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इंडिया ब्लॉक की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग ले रहे हैं। कांग्रेस और डीएमके, जो इंडिया ब्लॉक के भीतर लंबे समय से सहयोगी हैं, के बीच स्पष्ट तनाव के बावजूद, राउत ने 2029 के आम चुनावों से पहले गठबंधन को मजबूत करने के लिए शिवसेना (यूबीटी) की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा कि आज दिल्ली में हो रही इंडिया ब्लॉक की बैठक में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। शिवसेना (यूबीटी) इंडिया गठबंधन की एक प्रतिबद्ध सदस्य बनी रहेगी। हमारा निरंतर रुख रहा है और आगे भी रहेगा कि इंडिया ब्लॉक को और अधिक एकजुट और मजबूत होना चाहिए। हम देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे और 2029 में सार्थक बदलाव लाएंगे।

इंडिया ब्लॉक मीटिंग से ठीक पहले दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर वॉर

सोमवार को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी में पोस्टरों की एक नई जंग छिड़ गई। दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए पोस्टर दिखाई दिए। इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 23 विपक्षी दलों के नेताओं की नई दिल्ली में बैठक से कुछ घंटे पहले अशोक रोड के पास और शहर भर के कई चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से संबंधित कई विपक्षी नेताओं के बयान दिखाए गए थे, जिनमें एनसीपी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल थे। ये सभी बयान राहुल गांधी के खिलाफ है जो ये नेता पहले दे चुके हैं। राजधानी से सामने आए दृश्यों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीपीआई (एम) के नेताओं और अन्य प्रमुख विपक्षी हस्तियों की तस्वीरें वाले पोस्टर भी दिखाई दिए।

इंडिया ब्लॉक मीटिंग से पहले भाजपा का वार

अंदरूनी कलह से घिरा गठबंधन आप भी हुई खिलाफ

नईदिल्ली। सोमवार को होने वाले इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले, भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए इसे काल्पनिक बताया, जिसमें ज़मीनी स्तर पर एकता और दृढ़ विश्वास की कमी है। इंडिया ब्लॉक के बैनर तले बने 23 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रमुख क्षेत्रीय दलों, टीएमसी और डीएमके की हार के बाद आंतरिक मतभेदों को दूर करने के लिए बैठक करने की उम्मीद है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों, जिनमें डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और वामपंथी दल शामिल हैं, के बीच बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए दावा किया कि गठबंधन विघटन की ओर अग्रसर है। एक्स पर एक पोस्ट में पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के गठबंधन के पीछे के मकसद पर भी सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि डीएमके बनाम कांग्रेस, जेएमएम बनाम कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा कांग्रेस पर हमले के बाद इंडिया गठबंधन के पूरी तरह से बिखर जाने के बाद, अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को निशाना बनाया है। उसने छोटे क्षेत्रीय दलों को सलाह दी है कि कांग्रेस उनके साथ सिर्फ खुद को मजबूत करने के लिए गठबंधन कर रही है, न कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, और इसलिए वह इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगी।

उन्होंने पोस्ट किया कि इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं है। यह महज लोगों की

कल्पना है। दिखावटी बैठकें होती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कभी नज़र नहीं आती। गठबंधन पर साझा एजेंडा न होने का आरोप लगाते हुए पूनावाला ने कहा कि इसमें न कोई मिशन है, न कोई विज़न, सिर्फ फूट है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। यह हमेशा भ्रम, महत्वाकांक्षा और विभाजन का ही केंद्र रहा है। ये विभाजन अब हर दिन देखने को मिल रहे हैं। यहां तक कि जब ये पार्टियां एक साथ आईं, तो उन्होंने दृढ़ विश्वास के कारण नहीं बल्कि सुविधा के लिए ऐसा किया।

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी) के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को कांग्रेस के साथ मतभेदों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य कई दलों की इंडिया ब्लॉक की बैठक में उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह दर्शाता है कि गठबंधन एक-दूसरे की कमियों को छिपाने का माध्यम है। पत्रकारों से बात करते हुए पासवान ने कहा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने पर उन्हें आश्चर्य हुआ है। चिराग ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा ममता बनर्जी की आलोचना का जिक्र किया।

खेल
प्रमुख समाचार

ऑस्ट्रेलिया ओपन : सिंधू की निगाह खिताब पर

सिडनी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू मंगलवार से यहां शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में लंबे समय से चले आ रहे खिताब के सूखे को खत्म करने की कोशिश करेंगी, जबकि उभरते सितारे आयुष शेट्टी पुरुष एकल में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधू 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल जीतने के बाद से अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीतने की कवायद में हैं।

पूर्व विश्व चैंपियन का इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनवरी में मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचना रहा है। सिंधू को यहां अनुकूल ड्रॉ मिला है। इस 30 वर्षीय खिलाड़ी का पहला मैच पेरू की इनेस लूसिया कैस्टिलो से होगा। इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद उनका सामना हमवतन इशारानी बरुआ और चीन की हान कियान शी के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। सिंधू पिछले सप्ताह इंडोनेशिया ओपन में राउंड-ऑफ-16 में पहुंची थी जहां उन्हें विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आन से-यंग से हार का सामना करना पड़ा था।

अगर सिंधू सेमीफाइनल तक पहुंचती है तो वहां उनका सामना जापान की विश्व में तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची से हो सकता है। फाइनल में उनका मुकाबला थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त पोर्नपावी चोचुवोंग से हो सकता है। महिला एकल ड्रॉ में ही तन्वी शर्मा का सामना चीनी ताइपे की पांचवीं वरीयता प्राप्त चियू पिन-चियान से, जबकि मालविका बंसोड़ का मुकाबला मलेशिया की गोह जिन वेई से होगा।

अनमोल खरब को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन और चौथी वरीयता प्राप्त नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। आकर्षी कश्यप का मुकाबला मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से, जबकि तान्या हेमंत का अमेरिका की इशिका जायसवाल से होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 719 अंक टूटा निफ्टी 23,123 पर बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसका प्रमुख कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और वैश्विक बाजारों में कमजोरी रहा। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। दिन के कारोबार के अंत में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही लाल निशान में बंद हुए और व्यापक स्तर पर बिकवाली देखने को मिली। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 243.70 अंक यानी 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,123 पर बंद हुआ। पूरे दिन बाजार में उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन अंतत: बिकवाली हावी रही। बीएसई सेंसेक्स भी दबाव में रहा और 719.08 अंक यानी 0.97 प्रतिशत टूटकर 73,524.26 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक इक्विटी बाजारों में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर घरेलू बाजार पर साफ दिखाई दिया।

तीन महीनों में दूसरी बार बढ़े एलपीजी के दाम

नईदिल्ली। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने इसे वैश्विक परिस्थितियों की मजबूरी बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ऊर्जा कीमतों में तेजी, महंगा ट्रांसपोर्टेशन, बढ़ी बीमा लागत और सप्लाई संबंधी चुनौतियों के कारण एलपीजी की लागत में भारी वृद्धि हुई है। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर भारी नुकसान हो रहा था ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी को टालना संभव नहीं था। पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले यह बढ़ोतरी 7 मार्च को 60 रुपए की गई थी। हालिया बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 940 रुपए के पार पहुंच गई हैं।

अडानी पोर्ट्स को मिला एलएनजी निर्यात परियोजना के लिए ठेका

नई दिल्ली। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) को अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यात परियोजना के लिए 10 वर्ष का समुद्री सेवाओं का ठेका मिला है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही कंपनी ने दक्षिण अमेरिका में प्रवेश किया है और अपने अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवाओं के दायरे का विस्तार किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि यह ठेका एपीएसईजेड की अनुषंगी कंपनी (स्टेप-डाउन) अडानी हार्बर इंटरनेशनल एफजेडसीओ को अर्जेंटीना स्थित मेरिडियन ग्रुप के साथ एक संघ के जरिये दिया गया है। यह ठेका सदर्न एनर्जी एसए (सेसा) द्वारा आयोजित वैश्विक प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के बाद मिला है। कंपनी ने कहा कि इस अनुबंध से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला में उसकी मौजूदगी मजबूत होगी।

रसोई गैस के 50 हजार कनेक्शन होंगे निलंबित

आगरा। आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति के साथ एलपीजी कनेक्शन भी है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर पूर्ति विभाग ने दोहरे कनेक्शन वाले 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं का एलपीजी कनेक्शन निलंबित करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पीएनजी और एलपीजी दोनों के डाटाबेस का आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में नए पीएनजी कनेक्शन देने का काम भी तेज कर दिया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आनंद कुमार ने बताया कि जिले में कुल 87 गैस वितरक हैं और करीब 13.57 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं। इनमें 3.40 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हैं। वहीं, शहर में 75 हजार से अधिक पीएनजी उपभोक्ता भी हैं।

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया के चक्कर में फंसी अर्थ-व्यवस्था

सनत जैन

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आज देश में एक गंभीर बहस चल रही है। एक पक्ष का मानना है, कि 2004 से 2014 के बीच, विशेषकर 2011 तक, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। उस दौर में भारत की तुलना चीन, अमेरिका, रुस एवं अन्य यूरोपीय देशों के साथ वैश्विक मंचों पर होने लगी थी। सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों के विस्तार ने देश को नई आर्थिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान जब अमेरिका और यूरोप की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संकट से जूझ रही थीं, तब भारत अपेक्षाकृत मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ खड़ा दिखाई दिया। अनेक अर्थशास्त्रियों का मानना था, भारत के विशाल घरेलू बाजार, असंगठित क्षेत्र तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण था, उस समय भारत को वैश्विक आर्थिक क्षेत्र के केंद्र बिन्दू के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन 2011 के बाद भारत का राजनीतिक माहौल तेजी से बदला। भ्रष्टाचार के आरोप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्टों तथा अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले जनलोकपाल आंदोलन ने तत्कालीन सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। सरकार की छवि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जाता है। कारपोरेट जगत भी मनमोहन सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस तरह से सारा विपक्ष कांग्रेस और मनमोहन के खिलाफ खड़ा हो गया था। अंतत: 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ। आलोचकों का आरोप है कि उस समय देश की आडिट रिपोर्ट में लगाए गए कई आर्थिक

नुकसान के अनुमान न्यायिक प्रक्रिया में प्रमाणित नहीं हो सके, काल्पनिक आरोपों से तब तक राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसी नीतियाँ अपनाई गईं, जिनसे बड़े कॉर्पोरेट समूहों को लाभ मिला, जबकि लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नोटबंदी, जीएसटी के प्रारंभिक क्रियान्वयन और महामारी के प्रभाव ने छोटे व्यवसायों की कमर तोड़ दी। लाखों सूक्ष्म इकाइयाँ बंद हुईं। रोजगार के अवसर सिमटते चले गए। अर्थ- व्यवस्था में एक अन्य चिंता भारत के बढ़ते आयात और घटती विनिर्माण क्षमता को लेकर है। चीन से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक उत्पादों का आयात लगातार बढ़ा है। इसके विपरीत भारत की निर्यात वृद्धि अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है। जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता के दावों पर भी प्रश्नचिह्न लगा है। बढ़ती बेरोजगारी, महँगाई और घरेलू ऋण चिंता के विषय बने हुए हैं। किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान कर्जदार और खेती मंहगी होती जा रही है। आम नागरिक की क्रय-शक्ति घट गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और आवश्यक सेवाएँ लगातार महँगी होती जा रही हैं। दूसरी ओर, शेयर बाजार में तेजी और कॉर्पोरेट मुनाफों के बावजूद आम जनता की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर बढ़ गया है। आम आदमी की आय में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति बनी हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक नीतियों का केंद्र केवल बड़े निवेश और कॉर्पोरेट लाभ न होकर रोजगार सृजन, लघु उद्योगों का संरक्षण, कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा घरेलू मांग में विस्तार हो। भारत की वास्तविक शक्ति उसके करोड़ों छोटे उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग में निहित है। यदि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचता, तो ऊँची विकास दर का सपना- सपना बनकर ही रह जायेगा।भारत के सामने चुनौती केवल विकास दर बढ़ाने की नहीं, बल्कि समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने की है।

'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग

अभिनेत्री कंगना संग सीएम साय ने देखी फिल्म

रायपुर। आगामी 12 जून को रिलीज होने जा रही फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की विशेष स्क्रीनिंग सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जोरा स्थित द मॉल में आयोजित की गई। इस अवसर पर फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कंगना रनौत विशेष रूप से मौजूद रहीं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ फिल्म देखने पहुंचे। कार्यक्रम में फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया सहित फिल्म से जुड़े कलाकार और अन्य सदस्य भी शामिल हुए।

इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। स्क्रीनिंग के दौरान कंगना रनौत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म को लेकर अपने विचार साझा किए।

कंगना साझा किया अनुभव

फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान मुख्य अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ देखा। मुख्यमंत्री ने कलाकारों और फिल्म से जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्देशक भी छत्तीसगढ़ से हैं, इसलिए यह उनके लिए एक विशेष अनुभव रहा।

कंगना ने कहा कि आमतौर पर हम कर्मचारियों को सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन इस किरदार को निभाने के बाद उनकी मेहनत, समर्पण और जिम्मेदारियों का वास्तविक एहसास हुआ। भारत के प्रति लोगों में कितना गहरा प्रेम और समर्पण है, यह भी इस फिल्म के माध्यम से सामने आता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। कंगना ने बताया कि जब उनकी बातचीत फिल्म निर्देशक मनोज तापड़िया से हुई तो उन्हें एक बात विशेष रूप से पता चली कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।

एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की पहली स्क्रीनिंग में शामिल होंने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत आज रायपुर पहुंची. स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पद्मश्री और विधायक अनुज शर्मा, महापौर मीनल चौबे समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक्ट्रेस का स्वागत किया.जोरा द मॉल में फिल्म भारत भाग्य विधाता की पहली स्क्रीनिंग होगी. इसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत अन्य भाजपा नेता भी शामिल होंगे. फिल्म के निर्देशक मनोज तापड़िया भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और मीडिया एवं दर्शकों से बातचीत करेंगे.बता दें कि यह फिल्म मुंबई आतंकी 26/11 हमले के बाद स्वास्थ्य, सुरक्षा कर्मचारियों की बहादुरी को दर्शाती है. शहर में इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है. फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक जगत के के दिग्गज एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं।

सीएम ने की फिल्म की सराहना

फिल्म भारत भाग्य विधाता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनेत्री कंगना रनौत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। फिल्म में कंगना ने एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सीएम साय ने कहा कि यह फिल्म लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी और विपरीत परिस्थितियों में साहस, कर्तव्यनिष्ठा तथा मानवता का परिचय कैसे दिया जाता है, इसका सशक्त संदेश देती है।

टाटीबंध चौक से रेलवे स्टेशन तक फिर दौड़ेंगी आठ मिनी सिटी बसें

रायपुर। रायपुर शहर में आठ नई मिनी सिटी बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी। ये बसें टाटीबंध चौक से रेलवे स्टेशन और पचपेड़ी नाका होते हुए आईएसबीटी तक चलेंगी। यात्रियों के लिए टाटीबंध से रेलवे स्टेशन तक किराया 25 रुपये तय किया गया है। संचालन की शुरुआत 45 दिनों के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है। बसें हर 15 से 20 मिनट में उपलब्ध होंगी, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। शहरवासियों को इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसके लिए दो रूट तय किए गए है जिनमें पहला रूट टाटीबंध चौक से शुरू होकर आमापारा होते हुए रेलवे स्टेशन तक रहेगा। वहीं दूसरा रूट अंतरराज्यीय बस स्टैंड भांटागांव से शुरू होकर संतोषी नगर चौक होते हुए पचपेड़ी नाका चौक, सिद्धार्थ चौक, कालीबाड़ी और घड़ी चौक से रेलवे स्टेशन तक का है। बसों में यात्रा के लिए लगभग दो रुपये प्रति किलोमीटर का किराया लगेगा। इन मिनी बसों का उद्देश्य शहर के भीतर आवागमन को सरल बनाना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना है। बसों के संचालन से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। ये बसें शुरुआती दौर में सुबह साढ़े छह बजे से चलेंगी। ट्रायल के तौर पर बसें फिलहाल दो रूटों पर चलेंगी।

रेरा से अविनाश, वॉलफोर्ट, सिंघानिया समेत 6 सौ बिल्डर्स को जारी किया नोटिस

रायपुर। रेरा ने आवासीय-व्यावसायिक परियोजनाएं पूर्ण करने के बाद भी स्थानीय रहवासियों को प्रबंधन का हस्तांतरण नहीं करने पर प्रदेश के करीब 600 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इन बिल्डरों में रायपुर के अविनाश ग्रुप, सिंघानिया बिल्डकॉन, वालफोर्ट सहित अन्य बड़े बिल्डर शामिल हैं।

रेरा ने अलग-अलग स्तरों पर हुई शिकायत के बाद न सिर्फ निजी बिल्डरों को, बल्कि हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। इन्होंने भी अपनी कई परियोजनाओं के पूरा होने के बावजूद आधिपत्य नहीं सौंपा है।

रेरा के नियमों में स्पष्ट है कि आवासीय-व्यावसायिक परियोजना के पूरा होने पर नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद बिल्डरों को सामान्य क्षेत्र, सुविधाओं और प्रबंधन का हस्तांतरण आबंटितियों की समिति

अथवा संघ को करना जरूरी है। मगर बिल्डर ऐसा नहीं कर रहे हैं, यही नहीं कई बड़े बिल्डर स्वयं रखरखाव शुल्क ले रहे हैं।

रेरा ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा सहित अन्य जिलों के 595 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। उनकी 989 आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं को नोटिस दिया गया है। ये वे परियोजनाएं हैं, जिनका पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी कॉलोनी के प्रबंधन का हस्तांतरण आबंटितियों की समिति अथवा संघ को नहीं किया गया है। रेरा ने यह भी बताया कि अनेक मामलों में परियोजना पूर्ण होने के बाद भी प्रवर्तकों ने आबंटितियों की समिति या संघ का गठन सुनिश्चित नहीं किया और न ही सामान्य क्षेत्रों, सुविधाओं तथा संबंधित अभिलेखों का विधिवत हस्तांतरण किया। यह कार्रवाई भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(ई) और धारा 17 के तहत की गई है। जिन प्रमुख बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रायपुर के बिल्डकॉन, श्रीकृष्णा वाटिका महादेव घाट, सुमीत इंफ्रा रायपुर, विश्व भारती रायपुर, पारस बिल्डकॉन, संसार बिल्डकॉन, संकल्प बिल्डकॉन, साईनाथ बिल्डकॉन, रवि आहूजा, राजेश अग्रवाल, नीलम होम्स, दीपक रहेजा के अलावा रायपुर, भिलाई-दुर्ग और अन्य शहरों के कई बिल्डर शामिल हैं। सीजी रेरा ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम के तहत केवल प्रवर्तकों ही नहीं, बल्कि आबंटितियों की भी जिम्मेदारियां निर्धारित हैं।

नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बृजमोहन से की सौजन्य भेंट

रायपुर। रायपुर जिला अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस गरिमामय भेंट के दौरान अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने सांसद श्री अग्रवाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनकी शानदार जीत पर बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ दीं ।

उन्होंने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, वकीलों के हितों की रक्षा करने और युवा अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाएगी। इस गरिमामय मुलाकात के दौरान प्रमुख रूप से स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बृजेश पांडेय के नेतृत्व में अध्यक्ष दिनेश देवांगन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारती राठौर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त पटस्कार, सचिव राकेश पुरी, कोषाध्यक्ष रानी लक्ष्मी साहू, क्रीड़ा एवं संस्कृति सचिव युगेश्वर साहू, कार्यकारिणी सदस्य गुनेश निर्मलकर, नेहा राठौर, योगिराज वर्मा, अविजीत त्रिपाठी, विवेक मिश्रा, आकाश सोनी, योगिता धुरंदर, अमृता दीक्षित एवं आकाश जासूजा जी उपस्थित रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, न्याय व्यवस्था के सुचारू संचालन में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों, जल जीवन मिशन और खेल सुविधाओं की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने सुकमा जिले में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुख कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुकमा जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि प्रभावी कार्यशैली, नई तकनीकों के उपयोग और नियमित फील्ड मॉनिटरिंग से ही जनसमस्याओं का त्वरित समाधान संभव है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं का पूर्व आकलन कर समय रहते उनका समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पेयजल योजनाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल स्रोतों के क्लोरीनेशन, पानी टंकियों की साफ-सफाई और नल-जल योजनाओं के बेहतर संचालन-संधारण पर विशेष जोर दिया।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान श्री साव ने वर्षा ऋतु से पहले नालियों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूर्ण करने, पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मोदी सरकार ने 12 सालो में एक भी वादा पूरा नहीं किया: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने 12 सालो में एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा की हर गारंटी फेल, झूठी वादाखिलाफी और कोरी लफ्फाजी ही मोदी की गारंटी है। भाजपा ने अपने 2014 के घोषणापत्र में 25 करोड़ नौकरियां निर्मित करने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने माना कि 2014 के बाद से केवल 1.2 करोड़ नौकरियां निर्मित हुई हैं। यह मूल गारंटी का बीसवां हिस्सा भी नहीं है। वर्तमान में,

25 से कम आयु के दस में से चार स्नातक बेरोजगार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बेरोजगारों में से 83 परसेंट बेरोजगार युवा है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, महंगाई से देश के नागरिकों की कमर टूटती जा रही है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रुपये. का था, आज वह 1017 रु. के पार है वह भी मिल नहीं रहा। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 108 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 101 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। मोदी सरकार ने महंगाई से जूझ रही जनता एवं मंदी की मार झेल रहीं व्यवसायिक संस्थानों, उद्योगों पर कुठाराघात किया है।

अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री तत्काल समीक्षा बैठक बुलाये : शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी में लगातार लूट की घटना हो रही, चाकूबाजी की घटना हो रही, सरेआम चाकू मार कर हत्या कर दी जा रही, पुलिस क्या कर रही है? प्रदेश भर में हो रहे अपराध से राज्य का आम आदमी डरा सहमा है। राज्य की कानून व्यवस्था पर तथा अनियंत्रित अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री तत्काल समीक्षा बैठक बुलाये। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का

प्रयोग करके सरकार देख चुकी है, कमिश्नरी प्रणाली फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री अब तो बिगड़ते कानून व्यवस्था की जवाबदेही तय करे तथा गृह मंत्री को बर्खास्त करने की कार्यवाही करे। प्रदेश में थम ही नहीं रहा अपराधों का सिलसिला, कानून व्यवस्था फेल हो चुका है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लोगों की गोली मार कर हत्या हुई। अकेले राजधानी में 8 गोली कांड हुआ, बिलासपुर, कोटमी-पेंड्रा गौरेला, दुर्ग में, राजधानी रायपुर में, मस्तुरी, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवर्धा में लोगों को सरेआम गोली मार कर हत्या हुई। राजधानी के हीरापुर में सरेआम बम से हमला होता है। राजधानी के बिरगांव में बम बनाया जा रहा था। आपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो गये है कि उनमें पुलिस का भय जरा भी नहीं बचा है। राह चलते किसी को भी चाकू मार दी जा रही।

खाद संकट सरकार निर्मित आपदा किसान विरोधी नीतिः ठाकुर

रायपुर। खाद संकट को डबल इंजन सरकार निर्मित आपदा करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार बनने के बाद प्रदेश में हर वर्ष खाद संकट निर्मित हो रहा है। ये संकट 2024, 2025 एवं वर्तमान में भी जानबूझकर उत्पन्न किया गया है। ताकि किसानों की उत्पादन प्रभावित हो और सरकार वादानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने से बच सके। भाजपा सरकार की नीयत में

खोट है। बीते खरीफ सीजन में अधिकांश किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाये कम धान की खरीदी की गई है। जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा करने वाली डबल इंजन की सरकार की ये किसान विरोधी नीति है। बीते तीन खरीफ सीजन से बोआई के समय किसानों को खाद के लिए सोसायटियों के चक्कर लगवाये जा रहे है। किसान परेशान है और जिम्मेदार लोग सिर्फ खाद की कमी नहीं होने का दावा कर किसानों को गुमराह कर रहे है।प्रदेश में सहकारी सोसायटियों से खाद लेने वाले किसानों की संख्या करीब 33 लाख से अधिक है, इसके अलावा अधिया, रेगहा लेकर धान उत्पादन करने वाले एवं निजी दुकानों से खाद लेने वालों की संख्या लाखों में है।

स्कूल, कॉलेजों में शुल्क वृद्धि तत्काल वापस ले सरकारः वर्मा

रायपुर। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सरकारी स्कूलों और कॉलेज, विश्वविद्यालयों के शुल्कों में भारी वृद्धि का विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि यह सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व को कमाई का जरिया बनाना चाहती है, जिससे लाखों गरीब मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खत्म हो रहा है।

रविशंकर विश्वविद्यालय में परीक्षा और नामांकन फीस 46 प्रतिशत तक बढ़ा दिए गए हैं और अब हर साल 5 प्रतिशत शुल्क वृद्धि का छात्र विरोधी निर्णय इस सरकार ने लिया है। निजी स्कूल कॉलेज पहले से ही इस सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, अब सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों से भी यह सरकार अनुचित वसूली करना चाह रही है, हर विभाग को वसूली गिरोह की तर्ज पर चलाने का कुत्सित प्रयास जारी है। विगत दिनों सरकारी स्कूल और बोर्ड परीक्षा फीस में बढ़ोत्तरी की गई, माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस में बड़ा इजाफा किया गया, नियमित परीक्षा शुल्क 280 रुपये से बढ़ाकर 480 रु., मार्कशीट फीस 100 से 200 रुपए और प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) परीक्षा फीस 80 से बढ़ाकर 120 रूपय प्रति विषय कर दी गई।

कीमत बढ़ाकर जनता को लूट रही है सरकारः वंदना

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार अब रसोई गैस के बहाने जनता को लूट रही है और 12 साल में उसने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 530 रुपए की वृद्धि की है। मोदी सरकार ने पिछले चार महीनों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 89

रुपए की बढ़ोतरी की है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर 41 देशों से ईंधन विविधीकरण (फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन) की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी एलपीजी की किल्लत बनी हुई है।प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने सवाल किया कि 2025-26 में उज्ज्वला योजना के 5.56 करोड़ परिवारों ने केवल एक बार या एक भी बार रिफिल नहीं कराया। इनमें से 3.30 करोड़ परिवारों ने तो एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं लिया।प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने पूछा कि क्या यह स्थिति सरकार की नीतियों और बढ़ती कीमतों का परिणाम नहीं है। भाजपा नेता और पीएम मोदी पहले महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार को घेरते थे।

सुशासन तिहार 2026

सीएम साय ने की विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बालोद तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में संचालित विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। समीक्षा बैठक में कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजस्व प्रकरणों, ग्रामीण एवं शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था तथा विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविरों और चौपालों के माध्यम से सीधे लोगों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद प्रशासनिक अमले ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है और इस प्रतिबद्धता को आगे भी बनाए रखना होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को सकारात्मक सोच, जवाबदेही और जनसेवा की

भावना के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि शासन की किसी भी योजना का पात्र हितग्राही लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने दोनों जिलों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा नक्शा सुधार से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना तथा राजस्व अभिलेखों के अद्यतन कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले अधिकतम स्वीकृत आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाए, ताकि हितग्राहियों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अधिक से अधिक कारीगरों को मेसन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में पांच लाख सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाए तथा योजना से मिलने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी लाभों की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री साय ने खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के संबंध में किसानों को जागरूक किया जाए तथा इसके लाभों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र किसानों को योजना से लाभान्वित करने और एग्रीस्टैक पंजीयन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। धान उपार्जन और धान उठाव की समीक्षा करते हुए उन्होंने समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करने तथा स्थानीय स्तर पर राइस मिलों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक पहल करने को कहा।बिहान योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री निर्माण में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने तथा दोनों जिलों में इस कार्य को प्रारंभ करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति, कुपोषित बच्चों की संख्या और सुपोषण अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कुपोषण उन्मूलन के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.